RNI N.- BIHBIL/2022/88070

राष्ट्रीय द्विभाषिक सामाचार पत्र

www. bordernewsmirror.com

बॉर्डर न्यूज मिरर

"खबरों से समझौता नहीं"

पटना, वर्षः 7 , अंकः 160 , गुरुवार, 23 जुलाई 2026 मूल्यः 5:00, पृष्ठः8 9471060219, 9470050309 www.bordernewsmirror@gmail.com

पूर्वी चम्पारण बना ओवरऑल चैंपियन, खेल भवन में विजेता साइकिलिस्टों का भव्य सम्मान 03

ड्रोन तकनीक अपनाकर खेती को बनाएं लाभकारी, किसानों को दिया गया आधुनिक ... 04

प्रीति जिंटा ने साझा किया पति संग फीफा वर्ल्ड कप फाइनल की तस्वीरें 07

असम में बाढ़ से बिगड़े हालात, 'जल' जला

16 जिलों में 5.64 लाख लोग प्रभावित, 21 लोगों की मौत और कई लापता

गुवाहाटी (एजेंसी)। असम के कई जिलों में लगातार बारिश से हालात और बिगड़ गए हैं। बाढ़ से 21 और लोगों की मौत हो गई और लगभग 5.65 लाख लोग प्रभावित हुए। मंगलवार आधी रात को जारी असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की रोजाना बाढ़ रिपोर्ट के अनुसार, बिस्वनाथ, चराइदेव, धेमाजी, डिब्रूगढ़, गोलाघाट, जोरहाट, कामरूप, कामरूप मेट्रोपॉलिटन, कार्बी आंगलोंग, नागांव, शिवसागर और तिनसुकिया जिलों में 5,64,600 से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। इसमें आगे बताया गया है कि पिछले 24 घंटों में शिवसागर जिले में चार महिलाओं और दो बच्चों समेत 13 लोग बाढ़ के पानी में डूब गए।

इसके बाद चराइदेव में दो बच्चों समेत पांच लोग, गोलाघाट में दो लोग और जोरहाट में एक महिला की मौत हुई। इन मौतों के साथ इस साल बाढ़ से मरने वालों की कुल संख्या 31 हो गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने असम के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया है और अगले चार दिनों में कुछ जगहों पर

आंधी-तूफान और भारी बारिश का अनुमान जताया है। गुवाहाटी में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि मध्य असम और उससे सटे नगालैंड के ऊपर समुद्र तल से 1.5 से 3.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर बना चक्रवाती हवाओं का घेरा (साइक्लोनिक सर्कुलेशन) अब कमजोर पड़ गया है।

- **शिवसागर जिला सबसे ज्यादा प्रभावित-** शिवसागर सबसे ज्यादा प्रभावित जिला है, जहां लगभग 3.6 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। इसके बाद जोरहाट में लगभग 88,000 और चराइदेव में 72,500 से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में हैं। सोमवार रात से बाढ़ की स्थिति काफी बिगड़ गई है, जब 15 जिलों में लगभग 3.63 लाख लोग प्रभावित हुए थे। प्रशासन 10 जिलों में 273 राहत कैंप और राहत वितरण केंद्र चला रहा है, जहां अभी 12,284 विस्थापित लोगों की देखभाल की जा रही है। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस, पुलिस और सिविल एजेंसियों जैसे कई विभागों ने चराइदेव, गोलाघाट, जोरहाट और शिवसागर के अलग-अलग इलाकों से 6,000 से ज्यादा लोगों को बचाया है।

अडानी को मिलेगी एयरलाइन शुरू करने की इजाजत!

- **इंडिगो और एयर इंडिया का दबदबा तोड़ने की तैयारी में सरकार**

नई दिल्ली (एजेंसी)। सरकार एयरपोर्ट ऑपरेटर्स को एयरलाइन शुरू करने की अनुमति दे सकती है। इससे अडानी ग्रुप और जीएमआर एयरपोर्ट्स के एयरलाइन सेक्टर में उतरने का रास्ता साफ हो सकता है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस बारे में पॉलिसी में बदलाव करने पर विचार कर रही है। एयरलाइन सेक्टर में अभी इंडिगो और एयर इंडिया का दबदबा है जिसे सरकार तोड़ना चाहती है। इंडिगो की भारतीय बाजार में हिस्सेदारी 66.3 फीसदी पहुंच चुकी है। मौजूदा नियमों के तहत एयरपोर्ट ऑपरेटर किसी भी एयरलाइन में 10 फीसदी से ज्यादा हिस्सेदारी नहीं रख सकते। लेकिन अब इसे बदला जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय में इस पर विचार-विमर्श चल रहा है। किसी भी छूट के लिए कानून मंत्रालय और कैबिनेट की मंजूरी की जरूरत होगी। ओनरशिप से जुड़ी पाबंदियों में ढील मिलने से अडानी ग्रुप और जीएमआर एयरपोर्ट्स को एयरलाइन का मालिक बनने की इजाजत मिल जाएगी। अडानी ग्रुप अभी मुंबई एयरपोर्ट और सात अन्य एयरपोर्ट चलाता है। इसी तरह जीएमआर एयरपोर्ट्स दिल्ली एयरपोर्ट और देश के चार अन्य एयरपोर्ट को मैनेज करती है।

'पिछले एक दशक में 152 पेपर लीक हुए', राहुल गांधी बोले- शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग जायज

नईदिल्ली (एजेंसी)। राहुल गांधी और विपक्ष के तमाम नेताओं के सड़क पर उतरने की वजह से दिल्ली का सियासी माहौल बेहद गर्म है। सीजेपी के कार्यकर्ता शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं। जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के तमाम समर्थक जुटे हुए हैं। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने मंगलवार रात को सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से मुलाकात की। वांगचुक को मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मंगलवार रात को महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी सीजेपी के प्रदर्शन में पहुंचे। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, सांसद प्रियंका गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम बड़े नेता प्रधानमंत्री आवास के करीब धरने पर बैठ गए।

'छात्रों पर कार्रवाई न करने का भरोसा दे सरकार, खत्म कर दूंगा अनशन', सोनम वांगचुक ने मेदांता अस्पताल से लिखी चिट्ठी

सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने मोदी सरकार को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा है कि अगर छात्रों पर कार्रवाई न करने का भरोसा मिले तो अपना अनशन खत्म करने को तैयार हूं। सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के नाम चिट्ठी लिखी है।

छात्रों पर लाठीचार्ज का विरोध, संसद में कोहराम

- **खरगे बोले-धर्मेन्द्र प्रधान इस्तीफा दें, उसके बाद चर्चा करेंगे**
- **राहुल गांधी समेत कांग्रेस सांसद काले कपड़े पहनकर पहुंचे**

नई दिल्ली (एजेंसी)। संसद के मानसून सत्र के दौरान बुधवार को विपक्ष ने कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थकों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर हंगामा किया। हंगामे के बीच लोकसभा को गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। उधर राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि, वे सदन में नीट पेपर लीक मामले में चर्चा तभी चाहते हैं जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दें। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में कहा कि सरकार पिछले तीन दिनों से लगातार NEET पेपर लीक के मुद्दे पर चर्चा की पेशकश कर रही है। लेकिन विपक्ष मुद्दे पर राजनीति कर रहा है। राहुल गांधी समेत अन्य विपक्षी सांसद बुधवार को काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे। विपक्षी पार्टियां 20 जुलाई के संसद मार्च के दौरान छात्रों पर पुलिस कार्रवाई, पेपर लीक का विरोध कर रही हैं।

विपक्ष युवाओं को राजनीतिक हथियार न बनाए : राजनाथ

राजनाथ सिंह ने कहा- दिल्ली में जारी विरोध-प्रदर्शन गंभीर चिंता का विषय हैं। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और युवाओं को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे छात्रों की हर चिंता को सुनना और उसका समाधान करना हमारी जिम्मेदारी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारत के जागरूक, परिपक्व और विवेकशील युवा ऐसे भ्रामक प्रयासों को भली-भांति समझते हैं और वे प्रगति, विकास तथा राष्ट्रनिर्माण के मार्ग को ही चुनेंगे। हम इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि किसी भी व्यक्ति, विशेषकर हमारे छात्रों और युवाओं के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय न हो।

नड्डा बोले-

संसदीय मर्यादा को तार-तार किया जा रहा है

केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने राज्यसभा में कहा, IND। गठबंधन का व्यवहार बहुत गैर-जिम्मेदाराना है। हम संसद में उनके इस लोकतंत्र-विरोधी व्यवहार को साफ देख सकते हैं। संसदीय मर्यादा को तार-तार किया जा रहा है और लोकतांत्रिक मूल्यों का उल्लंघन हो रहा है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने अभी-अभी बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। इसके अलावा, हमारी सरकार NEET पेपर लीक और उससे जुड़े सभी मामलों पर भी चर्चा करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार पारदर्शी है। हमारी सरकार हमेशा लोगों के हित में काम करती है। इसलिए, हम उनकी (विपक्ष की) जन-विरोधी गतिविधियों की कड़ी निंदा करते हैं। वे लोकतंत्र या लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास नहीं करते हैं।

पटना में उग्र हुए छात्र, पुलिस ने किया लाठीचार्ज

- **बनारस में कांग्रेसियों को उठाया, भोपाल में विधायकों ने काली पट्टी बांधी**

पटना (एजेंसी)। नीट पेपर लीक के विरोध में दिल्ली के बाद देशभर में प्रदर्शन शुरू हो गए है। बुधवार को पटना पुलिस ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज किया। जवाब में भाजपा ने भी मोर्चा खोल दिया है। जबकि, यूपी के बनारस में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों को पुलिस उठाकर ले गई। इधर, मध्य प्रदेश में विधानसभा से लेकर सड़कों तक विरोध देखने को मिला। कांग्रेस के विधायक काली पट्टी बांधकर विधानसभा पहुंचे। उधर, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लोकभवन का घेराव किया। यूपी में लखनऊ समेत कई शहरों में सपा कार्यकर्ताओं ने पेपर लीक और दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस की मारपीट के खिलाफ प्रदर्शन किया। यूपी के ही नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद दिल्ली में 40 घंटे से धरने पर बैठे हुए हैं।

अयोध्या से जनकपुर का सफर होगा बेहद आसान

- **चंपारण के 49 गांवों से गुजरेगा फोर लेन राम-जानकी पथ**

मोतिहारी (एजेंसी)। मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम की जन्मस्थली अयोध्या व देवी जानकी के नगर जनकपुर को जोड़ने वाली महत्वाकांक्षी राम-जानकी पथ परियोजना अब पूर्वी चंपारण में गति पकड़ने लगी है। यह सड़क केवल परिवहन क्षेत्र की उपलब्धि नहीं, बल्कि धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से उत्तर बिहार की तस्वीर बदलने वाली मानी जा रही है। जिले में प्रस्तावित 56 किलोमीटर लंबी फोरलेन सड़क निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। पांच सदस्यीय कमेटी की जांच अंतिम चरण में है। अधिसूचना व खेसरा पंजी के निर्माण को लेकर तैयारी प्रारंभ कर दी गई है।

पीएम मोदी का एनडीए सांसदों को खास संदेश

युवाओं का भरोसा जीतें, विपक्षी 'साजिशों' का पर्दाफाश करें

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को एनडीए की बैठक में सांसदों से कहा कि युवाओं से संपर्क करें और उनकी चिंताओं को दूर करें और उन्हें इस बात से अवगत कराएं कि विपक्ष कैसे 'डर' फैलाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि पेपर लीक में जो भी शामिल हैं, उन्हें ऐसी सजा मिले कि फिर ऐसी घटना न हो। एनडीए सांसदों की बैठक की जानकारी रखने वाले लोगों के हवाले से एचटी ने एक रिपोर्ट दी है, जिसमें यह बताया गया है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नीट पेपर लीक की वजह से इस्तीफे की मांग को लेकर जो कुछ चल रहा है, उसको लेकर पीएम मोदी ने सत्ताधारी पक्ष के सांसदों से क्या कुछ कहा है। मंगलवार को हुई एनडीए बैठक के बारे में जानकारी रखने वाले एक व्यक्ति के अनुसार, युवाओं का विश्वास जीतने की जरूरत है..पेपर लीक होने की वजह से उन्हें बहुत ही दिक्कतें हुईं, लेकिन दोबारा परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के करवाई गई।

कश्मीर में आतंकी हमला

हेड कॉन्स्टेबल की मौत

- **अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा में तैनात थे, द रेजिस्टेंस फ्रंट ने जिम्मेदारी ली**

श्रीनगर (एजेंसी)। कश्मीर स्थित अनंतनाग जिले के लाल चौक इलाके में बुधवार को आतंकियों ने हमला किया। इसमें हेड कॉन्स्टेबल (35 साल) की मौत हो गई। अधिकारियों के मुताबिक दोपहर करीब 12.30 बजे आतंकियों ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों पर अचानक फायरिंग की।

सुरक्षाबलों ने जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद दोनों तरफ से गोलियां चलीं। इस दौरान हेड कॉन्स्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी जख्मी हो गए। उन्हें तुरंत सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

हमले के बाद आतंकी भाग गए। लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट ने हमले की जिम्मेदारी ली है। जिस जगह फायरिंग हुई, वह शहर का मुख्य बाजार है। यहां आम दिनों में भी काफी भीड़ रहती है।

- **सभी रास्तों पर नाकेबंदी, आतंकियों की तलाश तेज-** घटना के तुरंत बाद जम्मू-कश्मीर पुलिस, सेना और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे लाल चौक और आसपास के इलाके की घेराबंदी कर दी। अतिरिक्त सुरक्षा बल मौके पर भेजे गए और आतंकियों की तलाश में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। इलाके में आने-जाने वाले सभी रास्तों पर नाकेबंदी कर वाहनों और लोगों की गहन जांच की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि हमले में कितने आतंकी शामिल थे।

पूर्व अग्निवीरों को सीएपीएफ में मिलेगा 50 फीसदी आरक्षण

- **असम राइफल्स में भी मौका देने की तैयारी, केंद्र सरकार का ऐलान**

नई दिल्ली (एजेंसी)। गृह मंत्रालय ने मंगलवार को लोकसभा को बताया कि पूर्व अग्निवीरों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल्स में कॉन्स्टेबल (जनरल ड्यूटी) और राइफलमैन के पदों पर 50 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। एक लिखित सवाल के जवाब में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि सरकार ने इन पदों के लिए पूर्व-अग्निवीर नाम की एक नई कैटेगरी बनाई है। इसमें 50 प्रतिशत वैकेंसी का प्रावधान है, तय अधिकतम उम्र सीमा में तीन साल की छूट है और पूर्व-अग्निवीरों के पहले बैच के उम्मीदवारों के लिए तय उम्र सीमा से पांच साल की अतिरिक्त छूट है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सीएपीएफ कॉन्स्टेबल (जनरल ड्यूटी) और राइफलमैन पदों के लिए अप्लाई करने वाले पूर्व-अग्निवीरों को फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और लिखित परीक्षा से छूट दी जाएगी।

- **गृह मंत्रालय ने नियमों में किया बदलाव-** गृह मंत्रालय ने दिसंबर 2025 में एक नोटिफिकेशन जारी करके बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जनरल ड्यूटी कैडर (नॉन-गजेटेड) भर्ती नियम, 2015 में बदलाव किया था। इसके तहत कॉन्स्टेबल (जनरल ड्यूटी) के पदों पर पूर्व-अग्निवीरों के लिए कोटा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया। नोटिफिकेशन में कहा गया था, 'सीधी भर्ती (50 प्रतिशत सहित) के जरिए हर भर्ती वर्ष में पूर्व-अग्निवीरों के लिए वैकेंसी रिजर्व की जाएंगी। साथ ही सालाना वैकेंसी में पूर्व-सैनिकों के लिए 10 प्रतिशत और कॉम्बैटाइज्ड कॉन्स्टेबल (ट्रेड्समैन) के लिए 3 प्रतिशत तक जगह रिजर्व रहेगी।'

हूती विद्रोहियों की धमकी से डर गए भारत और चीन

- **दोनों देशों के टैंकरों ने रास्ता बदला, सऊदी से तेल ला रहे थे**

नई दिल्ली (एजेंसी)। सऊदी अरब का कच्चा तेल लेकर भारत और चीन जा रहे दो तेल टैंकरों ने मंगलवार को रेड सी (लाल सागर) में यू-टर्न लेकर अपना रास्ता बदल लिया। दोनों जहाज बाब-अल-मंदेब स्ट्रेट की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों की धमकी के बाद वापस स्वेज नहर की ओर मुड़ गए। दरअसल, हूती विद्रोहियों ने सोमवार को सऊदी अरब के खिलाफ नौसैनिक नाकेबंदी का ऐलान किया था। इसके बाद उन्होंने दुनियाभर की शिपिंग कंपनियों को ईमेल भेजकर चेतावनी दी कि सऊदी अरब के किसी भी बंदरगाह पर माल लादने या उतारने वाले जहाजों को उनकी सैन्य पहुंच के भीतर कहीं भी निशाना बनाया जा सकता है। रॉयटर्स के मुताबिक, इनमें से एक सुपर टैंकर 'शिन लॉन्ग यांग' सोमवार को सऊदी अरब के यनबू बंदरगाह से करीब 20 लाख बैरल कच्चा तेल लेकर चीन के लिए रवाना हुआ था।

रूसी हमले में 4 भारतीय नाविकों की मौत बर्दाश्त नहीं

विदेश मंत्री जयशंकर का रूसी विदेश मंत्री को दो टूक संदेश

मनीला (एजेंसी)। भारत ने रूस के सामने यूक्रेन युद्ध क्षेत्र में काम करने वाले भारतीय नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा रूस के सामने उठाया है। फिलीपींस की राजधानी मनीला में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ बातचीत के दौरान विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर भारत की 'गहरी चिंता' दोहराई है। यह बातचीत तब हुई जब दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और अहम क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा की। आपको बता दें कि दोनों नेताओं के बीच ये बैठक उस वक्त हुई है जब MV गोल्डन लियो नाम के जहाज पर रूस ने हमला किया था जिसमें चार भारतीय नागरिकों की मौत हो गई थी।

- **रूस के सामने भारत ने उठाया नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा-** जयशंकर ने आगे कि बैठक के दौरान हमारी साझेदारी के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई जिनमें व्यापार और निवेश, ऊर्जा और कनेक्टिविटी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और मोबिलिटी शामिल हैं। साथ ही यूक्रेन संघर्ष और खाड़ी क्षेत्र की स्थिति पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया। रूसी विदेश मंत्रालय ने भी एक्स पर एक पोस्ट में दोनों नेताओं के बीच बैठक की पुष्टि करते हुए कहा रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और भारत के विदेश मंत्री डॉ. सुब्रह्मण्यम जयशंकर ने मनीला में बातचीत की। यह बैठक मनीला में आसियान से जुड़ी विदेश मंत्रियों की बैठकों के दौरान हुई।

संक्षिप्त समाचार

30 जुलाई तक कई ट्रेनें लेट, टाइम बदला

हाजीपुर। प्रयागराज मंडल के कानपुर-टुंडला रेलखंड स्थित पनकी धाम स्टेशन पर यार्ड रिमॉडलिंग का कार्य किया जा रहा है। चौथी लाइन कनेक्टिविटी के लिए किए जा रहे नॉन-इंटरलॉकिंग (एनआई) कार्य के कारण इस रेलखंड से गुजरने वाली कई ट्रेनों के परिचालन समय में अस्थायी बदलाव किया गया है। 29 जुलाई, 2026 को बीकानेर से खुलने वाली 22308 बीकानेर-हावड़ा एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 150 मिनट की देरी से रवाना होगी। इसी दिन बाड़मेर से चलने वाली 12324 बाड़मेर-हावड़ा एक्सप्रेस भी 120 मिनट की देरी से खुलेगी। वहीं, 30 जुलाई, 2026 को आनंद विहार से चलने वाली 12816 आनंद विहार-पुरी नंदन कानन एक्सप्रेस तथा 12506 आनंद विहार-कामाख्या नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 150-150 मिनट की देरी से रवाना होंगी। इसके अलावा 12488 आनंद विहार-जोगबनी सीमांचल एक्सप्रेस 90 मिनट की देरी से चलेगी, जबकि 18101 टाटा-जम्मूतवी एक्सप्रेस भी 120 मिनट की देरी से अपने निर्धारित समय पर प्रस्थान करेगी। प्रयागराज मंडल में 22307 हावड़ा-बीकानेर एक्सप्रेस को 21 एवं 24 जुलाई को 100 मिनट नियंत्रित कर चलाया जाएगा। 12307 हावड़ा-जोधपुर एक्सप्रेस को 22 एवं 23 जुलाई को 100 मिनट नियंत्रित कर चलाया जाएगा। वहीं, 12505 कामाख्या-आनंद विहार नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस को 21 से 24 जुलाई तक प्रयागराज मंडल में 100 मिनट नियंत्रित कर संचालित किया जाएगा। 28 जुलाई को 12947 अहमदाबाद-राजगीर अजीमाबाद एक्सप्रेस, 12274 नई दिल्ली-हावड़ा एक्सप्रेस तथा 12566 नई दिल्ली-दरभंगा स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस को प्रयागराज मंडल में 60-60 मिनट नियंत्रित कर चलाया जाएगा।

8 सिपाहियों को एएसआई, 1 चालक हवलदार पद पर प्रोन्नत

हाजीपुर। हाजीपुर पुलिस केंद्र में मंगलवार को एक समारोह आयोजित किया गया। इसमें पुलिस अधीक्षक शुभांक मिश्रा ने 8 पीटीसी सिपाहियों को सहायक पुलिस अवर निरीक्षक (एएसआई) के पद पर पदोन्नत किया। इसके साथ ही, एक चालक सिपाही को हवलदार के पद पर प्रोन्नति मिली। एसपी ने सभी नव-पदोन्नत कर्मियों के कंधों पर स्टार लगाकर उन्हें सम्मानित किया। एसपी शुभांक मिश्रा ने सभी नव-पदोन्नत अधिकारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह पदोन्नति उनके उत्कृष्ट कार्य, समर्पण और अनुशासन का सम्मान है। एसपी ने यह भी जोड़ा कि नई जिम्मेदारी के साथ उनके कर्तव्य भी बढ़ गए हैं। एसपी मिश्रा ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे ईमानदारी, निष्पक्षता और कर्तव्यनिष्ठा के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें। उन्होंने आमजन के प्रति संवेदनशील और जवाबदेह पुलिसिंग सुनिश्चित करने पर जोर दिया। एसपी ने यह भी कहा कि पुलिस विभाग में अच्छा काम करने वाले कर्मियों को हमेशा प्रोत्साहित किया जाएगा। पदोन्नति पाने वाले जवानों ने पुलिस अधीक्षक को आश्वस्त किया कि वे पूरी निष्ठा के साथ अपनी नई जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। इस अवसर पर पुलिस केंद्र के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।

रील बनाते किशोरों ने स्कूटी को टक्कर मारी

हाजीपुर। हाजीपुर मार्ग पर बिदुपुर कमालपुर के निकट मंगलवार को एक सड़क हादसे में रामदौली हाई स्कूल के 68 वर्षीय नाइट गार्ड विश्वनाथ पंडित गंभीर रूप से घायल हो गए। आरोप है कि तेज रफ्तार R15 मोटरसाइकिल पर रील बना रहे दो किशोरों ने उनकी स्कूटी में टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हाजीपुर की ओर से आ रहे दो किशोर R15 बाइक पर 'लहरिया कट' का रील बना रहे थे। इसी दौरान उनकी बाइक विपरीत दिशा से आ रहे विश्वनाथ पंडित (पिता रामाशिस पंडित) की स्कूटी से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि वृद्ध गार्ड सड़क पर गिर पड़े और उन्हें गंभीर चोटें आईं। स्थानीय ग्रामीण अखिलेश सिंह और मुकेश कुमार सिंह सहित अन्य लोगों ने तुरंत घायल विश्वनाथ पंडित को बिदुपुर सीएचसी पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद, चिकित्सकों ने उनकी नाजुक हालत को देखते हुए उन्हें हाजीपुर सदर अस्पताल रेफर कर दिया। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने R15 मोटरसाइकिल सवार दोनों किशोरों को बाइक सहित पकड़ लिया। पूछताछ में किशोरों ने बताया कि वे नवादा के निवासी हैं और मथुरा स्थित अपनी नानी के घर जा रहे थे, तभी यह दुर्घटना हुई। स्कूल प्रशासन की ओर से प्रधानाध्यापक आभास सौरभ और अन्य शिक्षक घटना के बाद से सक्रिय हैं। उन्होंने बताया कि विश्वनाथ पंडित चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के पद पर कार्यरत थे और एक अवकाश प्राप्त कर्मी के स्थान पर नाइट गार्ड की ड्यूटी कर रहे थे। इसी बीच, बिदुपुर रेलवे स्टेशन रोड पर एक अन्य घटना में एक अज्ञात चार पहिया वाहन ने बाइक सवार दो युवकों को टक्कर मार दी। इस हादसे में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें बिदुपुर सीएचसी से हाजीपुर सदर अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही है।

वैशाली में बाल विवाह समाप्ति पर संकल्प सभा

हाजीपुर। वैशाली के भगवानपुर प्रखंड स्थित पीएम श्री जी.ए. उच्च विद्यालय, प्रतापतांड में बाल विवाह उन्मूलन पर एक जागरूकता कार्यक्रम और संकल्प सभा का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य समाज में बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति के प्रति जागरूकता बढ़ाना था।यह कार्यक्रम स्वर्गीय कन्हाई शुक्ला सामाजिक सेवा संस्थान और जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हुआ। विद्यालय के प्राचार्य जयप्रकाश ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की, जबकि अधिकार मित्र संतोष कुमार ने इसका संचालन किया।स्वर्गीय कन्हाई शुक्ला सामाजिक सेवा संस्थान के सचिव और जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन के निदेशक डॉ. सुधीर कुमार शुक्ला ने बाल विवाह के गंभीर परिणामों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि यह बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और उज्ज्वल भविष्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। डॉ. शुक्ला ने जोर देकर कहा कि बाल विवाह रोकना केवल प्रशासन की नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति की नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने अभिभावकों से बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने और उन्हें इस कुप्रथा से दूर रखने की अपील की। अधिकार मित्र संतोष कुमार ने बाल विवाह के सामाजिक, शारीरिक और मानसिक दुष्प्रभावों का विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने इसे बच्चों के अधिकारों का हनन बताया। उन्होंने छात्र-छात्राओं और ग्रामीणों से बाल विवाह के विरुद्ध जागरूक रहने और ऐसी किसी भी घटना की सूचना तुरंत संबंधित अधिकारियों को देने का आह्वान किया। विद्यालय के प्राचार्य जयप्रकाश ने बच्चों को संबोधित करते हुए उनसे अपने माता-पिता और समाज को इस कुप्रथा के खिलाफ जागरूक करने का आग्रह किया। उन्होंने छात्रों से अपनी पढ़ाई को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात कही।कार्यक्रम के अंत में, पीएलभी चंद्रशेखर कुमार, शिक्षक नीतीश कुमार, गोपालजी श्रीवास्तव, श्रीराम कुमार, चंदेश कुमार मौर्या, दीप्ती चक्रवर्ती, डॉली गुप्ता, रेशमा नासरीन सहित सभी शिक्षकों और छात्र-छात्राओं ने बाल विवाह मुक्त समाज बनाने का संकल्प लिया।

अनुकंपा पर बहाल चौकीदार का शराब पीते वीडियो वायरल

मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर के रामपुरहरि मॉडल थाना में अनुकंपा पर बहाल चौकीदार राम विजय कुमार का एक वीडियो सामने आया है। उनके साथ कुछ लोग बैठे हैं। टेबल पर गिलास और कुछ खाने-पीने की चीजें हैं। स्थानीय लोगों का दावा हैकि वीडियो रापुरहरि थाना के पास किसी होटल का है। चौकीदार अपने कुछ साथियों के साथ शराब पी रहे हैं। वीडियो में शराब की बोतल भी दिख रही है। रामपुरहरि थानाध्यक्ष अंजलि कुमारी ने बताया कि वीडियो देखा है, लेकिन उन्हें इस संबंध में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। मले की जांच सर्किल इंस्पेक्टर और डीएसपी स्तर से की जा रही है और जांच के बाद स्थिति स्पष्ट करेंगे। वहीं, सर्किल इंस्पेक्टर रंजन कुमार का कहना है कि प्रारंभिक जांच में वीडियो झारखंड के कोडरमा का लग रहा है। रामपुरहरि थाना क्षेत्र के आसपास जांच के दौरान वीडियो जैसा कोई होटल नहीं मिला। वीडियो में दिखाई दे रहे कुछ लोगों से फोन पर पूछताछ में भी उनके कोडरमा का रहने वाला होने की बात सामने आई है। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। इधर, एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने कहा कि वायरल वीडियो उनके संज्ञान में आया है। उन्होंने सर्किल इंस्पेक्टर और संबंधित डीएसपी को मामले की जांच का निर्देश दिया है। एसएसपी ने स्पष्ट कहा कि यदि जांच में वीडियो सही पाया गया और चौकीदार की संलिप्तता सामने आई, तो विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

सीएम हाउस के बाहर छात्रों पर लाठीचार्ज, पुलिस ने दौड़ाकर मारा

पटना की सड़कों पर पत्थबाजी कर रहे प्रदर्शनकारी, कई पुलिस वालों के सिर फटे

एजेंसी, पटना

NEET पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर बुधवार को मुख्यमंत्री आवास के बाहर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने दौड़ा-दौड़ाकर पीटा। इस दौरान कई छात्र सड़क पर लेट गए। पुलिस घसीटकर उन्हें अपने साथ ले गई। छात्रों को गाड़ियों में बैठाकर ले जाया गया।

इससे पहले पुलिस ने छात्रों को डाकबंगला चौराहे पर बैरिकेडिंग कर के रोका था। यहां करीब 1 घंटे तक छात्रों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बैरिकेंडिंग पर चढ़ गए। पुलिस ने कई बार उन्हें हटने को कहा, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। CISF और CRPF को छात्रों को हटाने के लिए बुलाया गया। छात्र बैरिकेडिंग तोड़कर यहां से राजभवन की ओर निकल गए।

डाकबंगला चौराहे से निकलने वाली बीजेपी नेताओं की गाड़ियों पर भी प्रदर्शनकारियों ने हमले किए। एक विधायक को जान बचाकर भागना पड़ा। प्रदर्शन के दौरान पटना IG की एस्कॉर्ट गाड़ी पर हमला हुआ।

DM-SP के समाने प्रदर्शनकारियों ने ताली बजाकर विरोध जताया। इससे पहले पुलिस ने छात्रों को जेपी गोलंबर पर रोका था, लेकिन वो वहां से भी बैरिकेडिंग तोड़कर डाकबंगला पहुंचे गए।

जेपी गोलंबर पर पुलिस ने छात्रों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। आंसू गैस से के गोले दागे। लाठीचार्ज भी किया, लेकिन इसके बाद भी वो सड़क पर बैठकर प्रदर्शन करने लगे। सुबह करीब 10.30 बजे गांधी मैदान से छात्रों ने अपना राजभवन मार्च शुरू किया था।

पटना में कांग्रेस और बीजेपी नेताओं में चले पत्थर-डंडे

पार्टियों के झंडे लेकर टूट पड़े, बीजेपी नेता बोले- कांग्रेसी पहले से लाठियां लेकर तैयार थे

एजेंसी, पटना

पटना में बुधवार को कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के बीच जमकर लाठी-डंडे चले। बीजेपी नेता कांग्रेस ऑफिस के सामने प्रदर्शन करने पहुंचे थे। इस दौरान दोनों ओर से डंडे चले, पत्थर चलाए गए। पुलिस इस दौरान चुपचाप खड़ी नजर आई।

बीजेपी नेताओं का आरोप है कि कांग्रेस नेता पहले से पत्थर और डंडे लेकर मारपीट के लिए तैयार बैठे थे। दोनों पार्टियों के बीच मारपीट के दौरान शुरुआत में पुलिस चुपचाप खड़ी नजर आई। इसके बाद मामला बढ़ने पर पुलिस ने एक्शन लिया।

बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी ने दुर्भावनापूर्ण मंशा के साथ पीएम आवास के सामने धरना प्रदर्शन कर हंगामा किया। कांग्रेस की ओर से देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की गई।

भाजपा ने कहा है कि गंभीर खतरे में डालने की कांग्रेस की प्रवृत्ति रही है। कांग्रेस राजनीतिक विरोधियों के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन करने जैसी निंदनीय परंपरा को बढ़ावा दे रही।

पटना पुलिस के टॉप-10 अपराधियों में शामिल नंदन महतो गिरफ्तार

एजेंसी, पटना

6 साल से था फरार डबल मर्डर से लेकर लूट-रंगदारी तक दर्ज हैं कई मामले

पटना पुलिस ने जिले के टॉप-10 वांछित अपराधियों में शामिल कुख्यात नंदन महतो को गिरफ्तार कर लिया है। छह वर्षों से फरार चल रहे नंदन महतो को गुप्त सूचना के आधार पर उसके पैतृक गांव नौबतपुर थाना क्षेत्र के अमरपुरा से दबोचा गया। गिरफ्तारी बिहटा और नौबतपुर थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में हुई। दानापुर-2 के डीएसपी अमरेंद्र कुमार झा ने बताया, 20 जुलाई की देर रात सूचना मिली थी कि बिहटा थाना के लूट, आर्म्स एक्ट और हत्या के प्रयास के मामलों में फरार नंदन महतो अपने गांव आया हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने छापेमारी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि नंदन महतो के खिलाफ पटना के विक्रम, दुल्हिनबाजार, नौबतपुर और बिहटा समेत कई थानों में डबल मर्डर, डकैती, रंगदारी, लूट, हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के एक दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं।

कई मामलों में वह लंबे समय से फरार चल रहा था। प्रारंभिक जांच में पुलिस को पता चला है कि नंदन महतो एक आपराधिक गिरोह का संचालन करता था। वारदात को अंजाम देने के बाद वह अपने साथियों के साथ दूसरे राज्यों में फरार हो जाता था, जिससे उसकी गिरफ्तारी लगातार टल रही थी।

प्रशांत किशोर की पार्टी दफ्तर पर इनकम टैक्स का छापा

एजेंसी, पटना

❐ पार्टी दफ्तर का तलाशी ले रही टीम, पीके के करीबी के होटल में भी रेड

बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के बीच जनसुराज प्रत्याशी प्रशांत किशोर के करीबी रवि नारायण सिंह के होटल में इनकम टैक्स का रेड की रेड पड़ी है। बताया जा रहा है कि प्रशांत किशोर की पार्टी दफ्तर पर भी इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। आईटी की टीम पार्टी दफ्तर का तलाशी ले रही है। दूसरी ओर जन सुराज पार्टी के नेताओं ने पटना पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी के प्रदेश सचिव रवि नारायण सिंह ने दावा किया कि पुलिस ने उनके होटलों और पार्टी कार्यकर्ताओं के ठिकानों पर लगातार छापेमारी की। इस दौरान पुराने गेस्ट रजिस्टर की मांग की गई। होटल सील करने और जेल भेजने की धमकी भी दी। रवि नारायण सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि पार्टी संस्थापक प्रशांत किशोर के ठहरने वाले होटल तक में पुलिस पहुंची और कार्यकर्ताओं को डराने-धमकाने की कोशिश की जा रही है।

पुलिस ने होटल का डिटेल मांगा: प्रदेश सचिव रवि नारायण सिंह के मुताबिक, सुबह 10 से 11 के बीच सबसे पहले स्पेशल सेल से फोन आया कि डिटेल चाहिए। हमने बताया कि पार्टी डिटेल देगी। इसके बाद पुलिस की ओर से जवाब आया कि हमें आपके होटल का डिटेल चाहिए। इसके बाद हमने डिटेल देने से मना किया। फिर पुलिस 19 जुलाई को हमारे होटल पहुंची और पुराने गेस्ट का डिटेल मांगी, लेकिन हमारे पास वह डिटेल उस वक्त उपलब्ध नहीं था। मैंने कहा कि हम 10 दिनों के बाद होटल की डिटेल उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि रजिस्टर दूसरे ऑफिस में है और बहुत पहले का मामला है। इसीलिए इसका डिटेल मिलना मुश्किल है। मैंने उन्हें आश्वासन भी दिया कि हम आपको डिटेल निकालकर जरूर भेज देंगे।

रजिस्टर देने से मना किया तो सील करने की दी धमकी- रवि नारायण सिंह: रवि नारायण सिंह के मुताबिक, जब रजिस्टर का डिटेल देने से मना किया, तब पुलिस वालों ने धमकी दी कि आपके होटल को हम पीयू में डालेंगे और घटनास्थल बनाएंगे। मुझे उस वक्त समझ में नहीं आया कि आखिर मामला क्या है? पुलिस वालों ने होटल सील करने की धमकी दी। रवि नारायण सिंह ने आगे बताया, 'मैंने उनसे साफ-साफ कहा कि हमारे होटल में कुछ गलत काम नहीं होता है। मुझे बस थोड़ा समय दीजिए। मैं आपको 10 दिनों के भीतर सारे रजिस्टर उपलब्ध करा दूंगा।'

सभी होटल पर की गई छापेमारी: रवि नारायण सिंह ने बताया, 'पुलिस वालों ने मेरे पूरे होटल की तालाशी ली, लेकिन उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगा। उसके बाद पुलिस की दूसरी यूनिट हमारे घर पहुंची। पुलिस वालों ने कहा कि आपके होटल में जो गेस्ट रुके हुए हैं, हमें उनकी तालाशी लेनी है। मेरे दो होटल हैं, दोनों ही होटल में पुलिस ने छापेमारी की।' रवि नारायण सिंह का आरोप है कि छापेमारी के दौरान बुद्धा कॉलोनी थाना के इंचार्ज दिनेश सिंह का फोन उनके पास आया और उन्होंने कहा कि आपके पार्टी के पैदा हुए चार दिन भी नहीं हुए हैं। उनकी ओर से अपशब्दों का भी प्रयोग किया गया।'

अरवल सिविल सर्जन पर हमले का राज्यभर में विरोध, सरकारी अस्पतालों में ओपीडी रहेगी बंद

एजेंसी, पटना

अरवल के सिविल सर्जन डॉ. राजकिशोर प्रसाद पर हुए हमले के विरोध में बिहार के सरकारी डॉक्टर बुधवार को राज्यभर के सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवाओं का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ (BHSA) ने इस एकदिवसीय विरोध कार्यक्रम का आह्वान किया है। BHSA का कहना है कि घटना के चार दिन बीत जाने के बाद भी न तो हमलावरों की गिरफ्तारी नहीं हुई है और न ही चिकित्सकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। उनकान ही अस्पतालों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कोई ठोस पहल की गई है। इससे राज्यभर के सरकारी डॉक्टरों में आक्रोश है।

हमले की निंदा, सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल: भासा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर अरवल के सिविल सर्जन पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। संघ का कहना है कि सरकारी अस्पतालों में कार्यरत चिकित्सकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रशासन और पुलिस की जिम्मेदारी है। यदि डॉक्टर खुद को असुरक्षित महसूस करेंगे तो

इमरजेंसी सेवाएं रहेंगी जारी

स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रतिकूल असर पड़ना स्वाभाविक है। संघ ने आरोप लगाया कि अब तक मामले में कोई प्रभावी प्रशासनिक या कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे चिकित्सकों का मनोबल प्रभावित हुआ है।

ओपीडी बंद, लेकिन इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेंगी: भासा के महासचिव डॉ. रोहित कुमार ने बताया, बुधवार को राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं पूरी तरह बंद रहेंगी। गंभीर मरीजों को हो, इसलिए आपातकालीन सेवाएं जैसे इमरजेंसी, प्रसव, आईसीयू और अन्य आवश्यक चिकित्सा सेवाएं पहले की तरह जारी रहेंगी।

मरीजों पर पड़ सकता है असर: डॉक्टरों के ओपीडी बहिष्कार का असर बुधवार को राज्य के जिला अस्पतालों, अनुमंडलीय अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में देखने को मिल सकता है। सामान्य मरीजों को इलाज के लिए परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि, स्वास्थ्य विभाग की ओर से इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वहीं भासा ने स्पष्ट किया है कि उनका आंदोलन मरीजों के खिलाफ नहीं, बल्कि सुरक्षित कार्य वातावरण और सम्मानजनक सेवा परिस्थितियों की मांग को लेकर है।

पटना समेत 8 जिलों में झमाझम बारिश 10 जिलों में आज हैवी रेन का अलर्ट

एजेंसी, पटना

नेपाल में बरसात से उफान पर कोसी और गंडक

मौसम विभाग ने आज बिहार के 10 जिलों के लिए हैवी रेन का अलर्ट जारी किया है। वहीं पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल और जहानाबाद में तेज बारिश हो रही है। कुछ जिलों में आसमान में बादल छाए हुए हैं। आज प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में मौसम सामान्य रहेगा। तापमान में 2 से 4 डिग्री तक बढ़ोतरी हो सकती है। 25 जुलाई के बाद पटना, समस्तीपुर, वैशाली, भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद और आसपास के जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। नेपाल में हो रही बारिश से कोसी और गंडक नदी उफान पर है।

मंगलवार को खगड़िया में तेज बारिश, जबकि पटना में बूंदाबांदी हुई। नालंदा, वैशाली समेत कई जिलों में बादल छाए हैं। सुबह सीतामढ़ी, कटिहार में बारिश हुई। मंगलवार को राजधानी पटना समेत राज्य के ज्यादातर हिस्सों में मंगलवार को दिनभर बादल छाए रहे। कुछ जिलों में रुक-रुककर बारिश होती रही। अधिकतम तापमान 35.2 डिग्री दर्ज किया गया।

लूट-अपहरण करने वाले 25-25 हजार के दो इनामी बदमाश गिरफ्तार

एजेंसी, पटना

❐ लूट-अपहरण मामलों में थे फरार, दिनदहाड़े लूटी थी ज्वेलरी शॉप

पटना पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने संयुक्त अभियान चलाकर दो इनामी अपराधियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित था और वे लंबे समय से फरार चल रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बाजार समिति निवासी रविशंकर कुमार और मसौढ़ी निवासी अमर प्रसाद सोनी के रूप में हुई है। दोनों के खिलाफ अलग-अलग थानों में गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं।

पुलिस के मुताबिक, 18 नवंबर 2022 को अमर प्रसाद सोनी ने अपने पांच अन्य साथियों के साथ मिलकर गर्दनीबाग थाना क्षेत्र स्थित एक ज्वेलरी दुकान में दिनदहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया था। आरोप है कि बदमाश करीब 2 लाख रुपये के गहने लूटकर फरार हो गए थे। साथ ही दुकान के जरूरी दस्तावेज भी अपने साथ ले गए थे।

घटना के बाद दुकानदार ने गर्दनीबाग थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। CCTV फुटेज के आधार पर अमर प्रसाद सोनी की पहचान हुई थी, लेकिन वह तब से फरार चल रहा था। पुलिस की डीआईयू (DIU) टीम ने उसे मसौढ़ी बाजार से गिरफ्तार किया। वहीं, दूसरा आरोपी रविशंकर कुमार पिछले तीन-चार वर्षों से एक अपहरण मामले में फरार चल रहा था। उसे STF ने पटना एयरपोर्ट थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। अधिकारियों के अनुसार, उनसे अन्य मामलों और उनके आपराधिक नेटवर्क के संबंध में भी जानकारी जुटाई जा रही है। पूछताछ के बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

महिलाओं-छात्राओं की सुरक्षा को लेकर 'पुलिस दीदी' अभियान शुरू, छात्राओं को किया जागरूक

एजेंसी, पटना

◆ मानव तस्करी से बचाव और सुरक्षा के दिए टिप्स

पटना के पालीगंज अनुमंडल क्षेत्र में बुधवार को बिहार पुलिस की महत्वाकांक्षी 'पुलिस दीदी' मुहिम की शुरुआत की गई। अभियान के तहत पालीगंज थाना की अभया ब्रिगेड टीम ने विभिन्न सरकारी विद्यालयों का दौरा किया। छात्राओं को महिला सुरक्षा, मानव तस्करी, साइबर अपराध और आत्मरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी।

छात्राओं को आत्मरक्षा, साइबर सुरक्षा की दी जानकारी: महिला पुलिस अधिकारियों ने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाली छात्राओं को जागरूक किया। उन्होंने बताया कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति के झांसे में आने से कैसे बचें। साथ ही उन्हें आपातकालीन स्थिति में तुरंत पुलिस हेल्पलाइन 112 पर संपर्क करने की सलाह दी गई। अभियान में स्थानीय प्रशासनिक पदाधिकारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं को आत्मरक्षा के बुनियादी उपाय, साइबर ठगी और सोशल मीडिया से जुड़े अपराधों से बचाव के तरीके भी बताए गए। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर बिना डर के पुलिस को सूचना दें।

क्या है 'पुलिस दीदी' मुहिम?: 'पुलिस दीदी' बिहार पुलिस की महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण से जुड़ी विशेष पहल है। इसके तहत महिला पुलिसकर्मियों की टीमें स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, महिला छात्रावास और अन्य संवेदनशील स्थानों पर पहुंचकर छात्राओं और महिलाओं को जागरूक करती हैं। साथ ही मनचलों पर निगरानी रखने और महिलाओं को सुरक्षा के प्रति जागरूक करने का भी काम करती हैं।

छात्राओं की सुरक्षा के लिए शुरू किया अभियान: पालीगंज थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह ने बताया, 'बिहार पुलिस और बिहार सरकार की पहल पर यह अभियान शुरू किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों की छात्राओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकारी विद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।' उन्होंने बताया कि छात्राओं को मानव तस्करी, साइबर अपराध और अन्य आपराधिक घटनाओं से बचाव के तरीके बताए गए। साथ ही अभिभावकों को भी जागरूक किया गया कि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत डायल-112 पर संपर्क करें।

पूर्वी चम्पारण बना ओवरऑल चैंपियन, खेल भवन में विजेता साइकिलिस्टों का भव्य सम्मान

बीएनएम@ सागर सूरज

गड़खा (सारण) में 18-19 जुलाई 2026 को आयोजित 18वीं राज्य रोड रेसिंग साइकिलिंग प्रतियोगिता में पूर्वी चम्पारण के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ओवरऑल चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर स्थानीय खेल भवन, मोतिहारी में जिला साइकिलिंग संघ की ओर से विजेता खिलाड़ियों के सम्मान में भव्य समारोह आयोजित किया गया। शहर के विभिन्न स्थानों पर भी समाजसेवियों ने खिलाड़ियों का गर्मजोशी से स्वागत किया। समारोह के मुख्य अतिथि जिला खेल पदाधिकारी अंकित कुमार तथा विशिष्ट अतिथि एसएसबी 71वीं वाहिनी, पिपरा कोठी के सब-डिप्टी कमांडेंट राकेश कुमार ने विजेता खिलाड़ियों को मेडल, ट्रॉफी एवं प्रशस्ति-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। इस अवसर पर जिला साइकिलिंग संघ के पदाधिकारियों ने भी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। प्रतियोगिता में सृष्टि कुमारी ने एक स्वर्ण एवं एक रजत पदक, सलोनी कुमारी ने एक स्वर्ण पदक, प्रियांशु कुमारी ने एक रजत पदक, रितिक कुमार ने एक स्वर्ण एवं एक रजत पदक तथा शौर्य कुमार ने एक रजत एवं एक कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके अलावा राजू शाह, मनोरंजन पटेल एवं अदिति कुमारी सहित अन्य खिलाड़ियों ने भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर जिले का मान बढ़ाया। जिला खेल पदाधिकारी अंकित कुमार ने खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि पूर्वी चम्पारण के युवाओं में खेल प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। खिलाड़ियों की यह उपलब्धि आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणास्रोत बनेगी तथा खेल विभाग उनकी हरसंभव सहायता करेगा।विशिष्ट अतिथि राकेश कुमार ने खिलाड़ियों के अनुशासन एवं खेल भावना की सराहना करते हुए कहा कि खेल युवाओं को राष्ट्र निर्माण के साथ शारीरिक एवं मानसिक रूप से सशक्त बनाते हैं। जिला साइकिलिंग संघ के अध्यक्ष एवं सचिव ने खिलाड़ियों के कठिन परिश्रम और प्रशिक्षकों के समर्पण की प्रशंसा करते हुए कहा कि सीमित संसाधनों के बावजूद पूर्वी चम्पारण के खिलाड़ियों ने राज्य स्तर पर परचम लहराकर यह साबित कर दिया है कि दृढ़ संकल्प और मेहनत से हर लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।सम्मान समारोह में खिलाड़ियों के चेहरे पर अपनी उपलब्धि की खुशी साफ झलक रही थी। उपस्थित अतिथियों ने सभी खिलाड़ियों को आगामी राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर जिला साइकिलिंग संघ के अध्यक्ष इंजीनियर अशोक कुमार, मुरारी पांडेय, रविंद्र यादव, रवि रंजन शर्मा, पूर्वी चम्पारण ग्रेपलिंग कुश्ती संघ के अध्यक्ष विनोद जायसवाल, नागदा सेवा समिति के अध्यक्ष मुन्ना गिरी, तलवारबाजी संघ के अध्यक्ष शुभम कुमार, बैडमिंटन संघ के सचिव दीपक कश्यप, समाजसेवी रंजीत गिरी, डॉ. मनीष कुमार सिंह, नेहा सिंह, विभिन्न खेल संघों के प्रतिनिधि, प्रशिक्षक, अभिभावक एवं बड़ी संख्या में खेल प्रेमी उपस्थित रहे।

मोतिहारी शिक्षा विभाग में प्रभारों को लेकर सवाल, क्या योजनाओं की करोड़ों की राशि को बंदरबाँट की हो रही तैयारी?

वरिष्ठ डीपीओ को स्थापना शाखा से हटाने पर विवाद, डीएम से आदेश रद्द करने की मांग; डीईओ बोले- जिला पदाधिकारी के अनुमोदन के बाद ही हुआ प्रभार परिवर्तन

» डीईओ के फैसले पर उठे सवाल, अधिकारी ने दिया जिलाधिकारी को आवेदन

बीएनएम@ सागर सूरज

मोतिहारी। पूर्वी चंपारण जिला शिक्षा कार्यालय में एक बार फिर प्रशासनिक फैसलों को लेकर विवाद गहरा गया है। अब तक जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों, लिपिकों और कथित बिचौलियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन इस बार स्वयं जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) राजन कुमार गिरी के आदेश सवालों के घेरे में हैं। स्थापना शाखा में किए गए हालिया प्रभार परिवर्तन को लेकर न केवल विभागीय नियमों की अनदेखी का आरोप लगाया गया है, बल्कि पूरे मामले की शिकायत जिलाधिकारी तक पहुंच गई है।

विवाद की शुरुआत उस समय हुई जब जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) गोपाल कृष्ण को स्थापना शाखा से हटाकर मध्याह्न भोजन (एमडीएम) का प्रभार सौंप दिया गया। इसके बाद डीईओ ने अलग आदेश जारी कर स्थापना शाखा का प्रभार दूसरे अधिकारी को सौंपने का निर्देश दिया।

गोपाल कृष्ण ने इस कार्रवाई को नियम विरुद्ध बताते हुए जिलाधिकारी सुमन सौरभ यादव को आवेदन देकर कार्यालय आदेश संख्या-1645, दिनांक 11 जुलाई 2026 को रद्द करने की मांग की है।

जिलाधिकारी को दिए आवेदन में गोपाल कृष्ण ने दावा किया है कि शिक्षा विभाग के पत्रांक-3119, दिनांक 27 अगस्त 2014 सहित विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुसार वरिष्ठ जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को स्थापना, सर्व शिक्षा अभियान अथवा लेखा जैसे महत्वपूर्ण शाखाओं का दायित्व दिया जाना चाहिए।

उन्होंने यह भी कहा है कि सामान्य परिस्थितियों में किसी पदाधिकारी का प्रभार दो वर्ष की अवधि पूरी होने से पहले नहीं बदला जाता, जब तक कोई विशेष प्रशासनिक आवश्यकता या शिकायत न हो।

शिकायत में कहा गया है कि उनके विरुद्ध न तो कोई आरोप है और न ही किसी प्रकार की प्रतिकूल टिप्पणी दर्ज है। इसके बावजूद उन्हें स्थापना शाखा से हटाकर एमडीएम भेज दिया गया।

जिला शिक्षा पदाधिकारी राजन कुमार गिरी ने अपना पक्ष भी रखा है। उन्होंने कहा कि जिला शिक्षा कार्यालय में किसी भी पदाधिकारी या कर्मी का प्रभार परिवर्तन अथवा पोस्टिंग जिला पदाधिकारी के अनुमोदन के बिना नहीं की जाती

आवेदन में इस कार्रवाई को विभागीय नीति, वरिष्ठता के सिद्धांत और सरकार के दिशा-निर्देशों के विपरीत बताया गया है।

यह भी दावा किया है कि स्थापना शाखा का कार्यकाल गोपाल कृष्ण द्वारा बिना किसी शिकायत के संचालित किया जा रहा था।

इसी बीच जिला शिक्षा कार्यालय में अन्य प्रशासनिक फेरबदल भी चर्चा का विषय बने हुए हैं। शिवनाथ विद्यार्थी को माध्यमिक शिक्षा एवं साक्षरता शाखा से हटाकर उनका पूरा प्रभार विनय कुमार को सौंप दिया गया है। वहीं स्थापना शाखा के प्रधान लिपिक अमित कुमार से बकाया निकासी का दायित्व वापस लेकर सत्यनारायण चौधरी को जिम्मेदारी दी गई है। लगातार हो रहे इन बदलावों को लेकर शिक्षा विभाग में तरह-तरह की चर्चाएं हैं।

शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि स्थापना, सर्व शिक्षा अभियान और लेखा जैसी शाखाओं के माध्यम से करोड़ों रुपये के वित्तीय मामलों का संचालन होता है। ऐसे में महत्वपूर्ण शाखाओं में बिना स्पष्ट कारण किए जा रहे प्रभार परिवर्तन कई सवाल खड़े कर रहे हैं।

उधर, पूरे विवाद पर जिला शिक्षा पदाधिकारी राजन कुमार गिरी ने अपना पक्ष भी रखा है। उन्होंने कहा कि जिला शिक्षा कार्यालय में किसी भी पदाधिकारी या कर्मी का प्रभार परिवर्तन अथवा पोस्टिंग जिला पदाधिकारी के अनुमोदन के बिना नहीं की जाती। संबंधित निर्णय को जिला पदाधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है और उसी के आधार पर आदेश जारी किए गए हैं।

अब पूरे मामले में दो अलग-अलग दावे सामने हैं। एक ओर शिकायतकर्ता विभागीय नियमों और वरिष्ठता के सिद्धांत का हवाला देकर आदेश को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जिला शिक्षा पदाधिकारी का कहना है कि सभी प्रशासनिक निर्णय जिला पदाधिकारी के अनुमोदन के बाद ही लिए गए हैं।

ऐसे में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि शिकायत पर जिलाधिकारी क्या निर्णय लेते हैं और क्या विभागीय प्रक्रिया एवं नियमों के अनुपालन की जांच कराई जाती है।

पूर्वी चंपारण में नई चीनी मिल की कवायद तेज, निरानी शुगर्स की तकनीकी टीम ने किया दो दिवसीय सर्वे

ढेकहा और पहाड़पुर में संभावित स्थलों का तकनीकी मूल्यांकन, गन्ना उत्पादन, भूमि, सड़क, बिजली व जल संसाधनों का किया गया आकलन

बीएनएम@ मोतिहारी

पूर्वी चंपारण में नई चीनी मिल की स्थापना की संभावनाओं को लेकर कवायद तेज हो गई है। इसी क्रम में 21 एवं 22 जुलाई 2026 को मेसर्स निरानी शुगर्स लिमिटेड, बेंगलुरु की तकनीकी टीम ने जिले के संभावित स्थलों का दो दिवसीय विस्तृत सर्वेक्षण किया। टीम ने मौजा ढेकहा (मोतिहारी) तथा प्रखंड पहाड़पुर क्षेत्र का निरीक्षण कर नई चीनी मिल स्थापना के लिए आवश्यक तकनीकी एवं आधारभूत सुविधाओं का आकलन किया। सर्वेक्षण के दौरान ईख पदाधिकारी, मोतिहारी, सहायक निदेशक (ईख विकास), अंचल अधिकारी तथा सहायक निदेशक (कीट) सहित विभागीय अधिकारियों ने तकनीकी टीम के साथ संयुक्त रूप से स्थल

निरीक्षण किया। इस दौरान उपलब्ध भूमि, सड़क संपर्क, जल संसाधन, विद्युत सुविधा, क्षेत्र में गन्ना उत्पादन, किसानों की उपलब्धता तथा अन्य आधारभूत संरचनाओं का गहन मूल्यांकन किया गया। विभागीय अधिकारियों ने तकनीकी टीम को क्षेत्र की कृषि एवं गन्ना उत्पादन से संबंधित विस्तृत जानकारी भी उपलब्ध कराई। दो दिवसीय तकनीकी सर्वेक्षण को पूर्वी चंपारण में नई चीनी मिल स्थापना की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। परियोजना के साकार होने पर गन्ना उत्पादक किसानों को स्थानीय स्तर पर अपनी उपज के विपणन की सुविधा मिलेगी, परिवहन लागत घटेगी तथा रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। साथ ही जिले के औद्योगिक और आर्थिक विकास को भी नई गति मिलने की उम्मीद है।

पीएम सूर्य घर योजना में सुस्ती पर डीएम सख्त, एक सप्ताह में 97 लाभुकों को ऋण राशि देने का निर्देश

दो सप्ताह में 142 लंबित आवेदनों के निष्पादन की समय-सीमा तय, बैंक, बिजली विभाग और वेंडरों को बेहतर समन्वय के निर्देश

बीएनएम@ मोतिहारी

प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने को लेकर बुधवार को जिलाधिकारी सौरभ सुमन यादव की अध्यक्षता में नगर के समाहरणालय में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक हुई। उक्त बैठक में बैंक ऋण स्वीकृति और राशि वितरण की धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताते हुए सभी बैंक अधिकारियों को तय समय-सीमा के भीतर लंबित मामलों का निष्पादन करने का निर्देश दिया। बैठक में कार्यपालक अभियंता (विद्युत विभाग), प्रभारी बैंकिंग पदाधिकारी, अग्रणी जिला प्रबंधक (एलडीएम), विभिन्न बैंकों के जिला समन्वयक तथा योजना से जुड़े पंजीकृत वेंडर मौजूद थे।समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि जिन 97 लाभुकों के

ऋण स्वीकृत हो चुके हैं, उन्हें एक सप्ताह के भीतर हर हाल में राशि का वितरण सुनिश्चित किया जाए। वहीं, 142 लंबित ऋण आवेदनों की जांच पूरी कर दो सप्ताह के भीतर स्वीकृति देने का निर्देश दिया गया। उन्होंने विद्युत विभाग, बैंक और वेंडरों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर सभी कागजी प्रक्रियाओं को समय पर पूरा करने पर जोर दिया, ताकि योजना का लाभ आम लोगों तक बिना किसी बाधा के पहुंच सके। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी संबंधित विभागों और बैंकों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए गए।

सदर अस्पताल में 10 बेड का आईसीयू सुदृढ़, पांच अनुमंडलीय अस्पतालों में डायलेसिस यूनिट का लोकार्पण

» पटना से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया वर्चुअल उद्घाटन, लाइव प्रसारण के जरिए मोतिहारी में भी कार्यक्रम का आयोजन

बीएनएम@ मोतिहारी

जिला सदर अस्पताल में गहन चिकित्सा इकाई (आईसीयू) का सुदृढ़ीकरण करते हुए इसे 4 शय्या से बढ़ाकर 10 शय्या का बनाया गया। वहीं जिले के पांचों अनुमंडलीय अस्पतालों में तीन-तीन शय्या वाले डायलेसिस यूनिट का लोकार्पण बुधवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना स्थित गुरु गोविंद अस्पताल से वर्चुअल माध्यम से किया। कार्यक्रम का लाइव प्रसारण पूरे बिहार के साथ मोतिहारी सदर अस्पताल में भी किया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिला स्तर से मरीजों के रेफरल की संख्या कम करना प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से पूर्व से संचालित चार शय्या वाले आईसीयू का सुदृढ़ीकरण कर उसे 10 शय्या तक विस्तारित किया गया है। उन्होंने बताया कि सदर अस्पताल में उपलब्ध अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं का भी गैप एनालिसिस कराया जा रहा है। इसके आधार पर आवश्यक सुविधाओं का चरणबद्ध तरीके से सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। कार्यक्रम में जिला पदाधिकारी सौरभ सुमन यादव, उपमहापौर डॉ. लाल बाबू गुप्ता, सिविल सर्जन डॉ. दिलीप कुमार, सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. एस.एन. सत्यार्थी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक ठाकुर विश्वमोहन, जिला योजना समन्वयक भारत भूषण, जिला अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पदाधिकारी मो. अमानुल्लाह सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

इग्नू में जुलाई सत्र के नामांकन शुरू, 31 जुलाई तक करें आवेदन

बीएनएम@ मोतिहारी

उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) ने जुलाई 2026 सत्र के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी है। आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के गांधी भवन स्थित इग्नू अध्ययन केंद्र (एलएससी-46040) में स्नातक, स्नातकोत्तर एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रारंभ हो चुका है। अध्ययन केंद्र के समन्वयक डॉ. श्याम नंदन ने बताया कि इग्नू का उद्देश्य समाज के प्रत्येक वर्ग तक गुणवत्तापूर्ण एवं सुलभ शिक्षा पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि जो विद्यार्थी आर्थिक, सामाजिक या व्यावसायिक कारणों से नियमित विश्वविद्यालयों में अध्ययन नहीं कर पाते, उनके लिए इग्नू एक बेहतर विकल्प है। यहां विद्यार्थी अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ाई करते हुए रोजगार, व्यवसाय या अन्य जिम्मेदारियों का निर्वहन भी कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि नई शिक्षा नीति

(एनईपी) के तहत छात्र-छात्राओं को ड्युअल डिग्री का भी अवसर मिल रहा है। इसके तहत किसी अन्य विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में नियमित रूप से अध्ययनरत विद्यार्थी भी इग्नू के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा में दूसरा पाठ्यक्रम कर सकते हैं। इग्नू की शिक्षा प्रणाली की विशेषता इसकी लचीली व्यवस्था है। विद्यार्थियों को नियमित कक्षाओं में उपस्थित रहने की अनिवार्यता नहीं होती। उन्हें स्व-अध्ययन सामग्री, ऑनलाइन संसाधन, डिजिटल लाइब्रेरी, ऑडियो-वीडियो व्याख्यान, शैक्षणिक परामर्श सत्र तथा अध्ययन केंद्रों के माध्यम से आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराया जाता है। कम शुल्क और गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री के कारण इग्नू नौकरीपेशा युवाओं, गृहिणियों, सरकारी कर्मचारियों तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों की पहली पसंद बनता जा रहा है। जुलाई 2026 सत्र में अंग्रेजी, हिंदी, इतिहास, राजनीति विज्ञान और संस्कृत विषयों में स्नातक (ऑनर्स) एवं नई शिक्षा नीति के तहत चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश उपलब्ध है। वहीं एम.ए. अंग्रेजी, हिंदी, इतिहास, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र एवं संस्कृत, एम.कॉम., एम.बी.ए. सहित डिजिटल मीडिया और अनुवाद जैसे रोजगारोन्मुखी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में भी नामांकन लिया जा रहा है। डॉ. श्याम नंदन ने कहा कि इग्नू केवल डिग्री प्रदान करने तक सीमित नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों को कौशल विकास और रोजगार की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करने पर भी विशेष जोर देता है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए यह उच्च शिक्षा प्राप्त करने का एक प्रभावी माध्यम बनकर उभरा है। इग्नू अध्ययन केंद्र (एलएससी-46040) ने क्षेत्र के विद्यार्थियों और अभिभावकों से अपील की है कि वे 31 जुलाई से पहले अपना नामांकन सुनिश्चित कर इस अवसर का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए इच्छुक विद्यार्थी महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, गांधी भवन, मोतिहारी स्थित इग्नू अध्ययन केंद्र (एलएससी-46040) अथवा अध्ययन केंद्र के समन्वयक डॉ. श्याम नंदन से संपर्क कर सकते हैं।

'पुलिस दीदी' टीम ने विद्यालयों में छात्रों को किया जागरूक, साइबर सुरक्षा व मानव तस्करी से बचाव की दी जानकारी

बीएनएम@ मोतिहारी

जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में बुधवार को "पुलिस दीदी" टीम द्वारा विद्यालयों में जागरूकता अभियान चलाकर छात्र-छात्राओं को मानव तस्करी, बाल श्रम, महिला सशक्तिकरण एवं साइबर अपराध से बचाव के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों को विभिन्न सामाजिक एवं कानूनी विषयों पर विस्तार से जानकारी दी गई। पुलिस द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, 22 जुलाई 2026 को जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में आयोजित कार्यक्रमों के दौरान छात्र-छात्राओं को साइबर ठगी से बचने के उपाय, मानव तस्करी की पहचान, बाल श्रम के दुष्परिणाम तथा महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी दी गई। अभियान के तहत "ऑपरेशन विधि पालक युवक" के अंतर्गत विद्यार्थियों को कानून का पालन करने, सामाजिक बुराइयों से दूर रहने तथा जिम्मेदार नागरिक बनने की शपथ भी दिलाई गई। कार्यक्रम में पुलिस अधिकारियों ने छात्रों से किसी भी संदिग्ध गतिविधि, साइबर अपराध या अन्य आपराधिक घटनाओं की जानकारी तत्काल पुलिस को देने की अपील की। साथ ही सुरक्षित इंटरनेट उपयोग, सोशल मीडिया पर सतर्कता तथा आपातकालीन स्थिति में पुलिस सहायता लेने के तरीकों की भी जानकारी दी गई। यह जागरूकता कार्यक्रम जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों के विद्यालयों में आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं एवं शिक्षकों ने भाग लिया। पुलिस का उद्देश्य बच्चों में कानूनी जागरूकता बढ़ाना तथा उन्हें सुरक्षित और जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित करना है।

एक पेड़ एक जिंदगी' अभियान में एसएसबी 71वीं वाहिनी के कमांडेंट बने मुख्य अतिथि, विद्यार्थियों को दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश

बीएनएम@ मोतिहारी

पर्यावरण संरक्षण और हरित भविष्य के निर्माण के उद्देश्य से चलाए जा रहे "एक पेड़ एक जिंदगी" अभियान के तहत मंगलवार को जवाहर लाल नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय, घोड़ासहन में भव्य वृक्षारोपण एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 71वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी), मोतिहारी के कमांडेंट प्रफुल्ल कुमार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत महाविद्यालय के प्राचार्य एवं शिक्षकों द्वारा कमांडेंट प्रफुल्ल कुमार का पुष्पगुच्छ एवं शॉल भेंट कर स्वागत और सम्मान के साथ हुई। इसके बाद उन्होंने प्राचार्य, शिक्षकों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों से संवाद करते हुए शिक्षा, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका पर अपने विचार साझा किए। अपने संबोधन में कमांडेंट प्रफुल्ल कुमार ने कहा कि वृक्ष केवल पर्यावरण संतुलन का आधार नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन, स्वास्थ्य और समृद्धि की अमूल्य धरोहर हैं। उन्होंने प्रत्येक नागरिक से

अपने जीवन में कम-से-कम एक पौधा लगाने और उसकी देखभाल का संकल्प लेने का आह्वान किया। साथ ही विद्यार्थियों से पर्यावरण संरक्षण को जन-आंदोलन बनाने तथा समाज को अधिक से अधिक वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करने की अपील की। उन्होंने युवाओं को राष्ट्र सेवा, अनुशासन, सामाजिक उत्तरदायित्व और पर्यावरण संरक्षण के प्रति सदैव जागरूक एवं प्रतिबद्ध रहने का संदेश देते हुए कहा कि अनुशासित और जागरूक युवा ही विकसित भारत की सबसे बड़ी ताकत हैं। इस दौरान कमांडेंट श्री कुमार ने महाविद्यालय परिसर में पौधारोपण कर "एक पेड़ एक जिंदगी" अभियान को अपना समर्थन दिया और सभी से पौधों के संरक्षण एवं नियमित देखभाल का संकल्प लेने का आग्रह किया। महाविद्यालय परिवार, छात्र-छात्राओं और उपस्थित अतिथियों ने भी पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम का समापन प्रेरणादायी वातावरण में हुआ। सभी प्रतिभागियों ने अधिक से अधिक वृक्ष लगाने और उनकी सुरक्षा का संकल्प लिया। एसएसबी की 71वीं वाहिनी ने भविष्य में भी पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक जागरूकता एवं जनसहभागिता से जुड़े जनहितकारी अभियानों में सक्रिय भूमिका निभाने की प्रतिबद्धता दोहराई।

सोनम वांगचुक के समर्थन में माकपा व ऑटो चालक संघ का प्रदर्शन, धर्मेंद्र प्रधान और प्रधानमंत्री का पुतला दहन

पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार पर साधा निशाना, आंदोलन तेज करने की दी चेतावनी

बीएनएम@ मोतिहारी

सोनम वांगचुक के समर्थन में मंगलवार को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) तथा ऑटो रिक्शा चालक संघ (सीटू), पूर्वी चंपारण के संयुक्त तत्वावधान में बलुआ चौक पर विरोध-प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन किया तथा उनके इस्तीफे की मांग उठाई। कार्यक्रम की शुरुआत बलुआ चौक पार्क से हुई, जहां पार्टी कार्यकर्ता सरकार विरोधी नारों के साथ जुलूस की शक्ल में ऑटो स्टैंड पहुंचे। वहां

पुतला दहन के बाद सभा आयोजित की गई। सभा को संबोधित करते हुए माकपा नेताओं ने आरोप लगाया कि देश में लगातार विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक हो रहे हैं और शिक्षा माफियाओं को केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्री का संरक्षण प्राप्त है। नेताओं ने कहा कि इन मुद्दों के विरोध में सोनम वांगचुक 19 दिनों से अनशन पर थे, लेकिन उन्हें बिना पूर्व सूचना के हिरासत में लेना लोकतंत्र पर हमला है।वक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि समय रहते न्याय नहीं मिला तो आंदोलन और अधिक उग्र होगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। सभा को माकपा के जिला मंत्री सत्येंद्र कुमार मिश्र, शक्तिनाथ तिवारी, ऑटो चालक संघ के जिला अध्यक्ष संजय गुप्ता, विपिन बिहारी दुबे, हमराज हाशमी, पप्पू शाह, दीपक शर्मा, सुरेंद्र मिश्र, प्रदीप सहनी, विकास कुमार, अशोक तिवारी, ध्रुव त्रिवेदी, फिरोज आलम समेत अन्य नेताओं ने संबोधित किया।

संक्षिप्त समाचार

नशाखुरानी का शिकार युवक 22 दिन बाद सकुशल घर लौटा

बीएनएम@ समस्तीपुर। मोहिउद्दीननगर थाना क्षेत्र के उत्तर पंचायत अंतर्गत बलुआही गांव निवासी विपिन महतो (पिता- रामप्रसाद महतो) नशाखुरानी गिरोह का शिकार होने के बाद करीब 22 दिनों तक लापता रहे। किसी तरह गिरोह के चंगुल से जान बचाकर घर लौटने पर परिजनों ने राहत की सांस ली। युवक के सकुशल वापस आने से पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। पीड़ित विपिन महतो ने बताया कि वह गुजरात के सूरत में मजदूरी करते थे और घर लौटने के लिए अहमदाबाद से बरौनी जाने वाली ट्रेन पकड़ने वाले थे। ट्रेन का इंतजार करने के दौरान उन्होंने स्टेशन के बाहर से गुटखा और सिगरेट खरीदी तथा स्टेशन परिसर में बेडशीट बिछाकर बैठ गए। इसी बीच एक अज्ञात व्यक्ति उनके पास आया और खुद को बिहार जाने वाला यात्री बताते हुए बातचीत करने लगा। कुछ देर बाद अचानक उन्हें तेज नींद आने लगी। विपिन का आरोप है कि उस व्यक्ति ने रूमाल से उनका चेहरा पोंछा, जिसके बाद वह पूरी तरह बेहोश हो गए। होश आने पर उन्होंने खुद को अहमदाबाद के एक अज्ञात स्थान पर पाया। उनका मोबाइल फोन, पर्स और नकदी गायब थी। विपिन ने दावा किया कि उन्हें करीब एक दर्जन लोगों ने अपने कब्जे में रखा था। उनके अनुसार, गिरोह के सदस्य संदिग्ध आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त थे।

एमयू से संबद्ध कॉलेजों में अतिरिक्त शुल्क वसूली पर रोक लगे : सूरज सिंह

बीएनएम@ गयाजी। मगध विश्वविद्यालय के छात्र नेता सूरज सिंह ने मगध विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों में नामांकन के दौरान छात्र-छात्राओं से प्रॉस्पेक्टस शुल्क, डेवलपमेंट शुल्क, प्रोसेसिंग शुल्क तथा अनिवार्य इंटर्नशिप के नाम पर अतिरिक्त राशि वसूले जाने पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि यह छात्रों के साथ आर्थिक शोषण है और शिक्षा के अधिकार की भावना के विपरीत है। उन्होंने कहा कि मगध विश्वविद्यालय में नामांकन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन हो चुकी है। जब छात्र-छात्राएं आवेदन के समय अपनी सभी आवश्यक जानकारियां ऑनलाइन उपलब्ध करा देते हैं, तब प्रॉस्पेक्टस के नाम पर अलग से शुल्क लेना पूरी तरह अनुचित और अव्यावहारिक है।सूरज ने कहा कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब अधिकांश महाविद्यालयों में छात्रों को शुद्ध पेयजल, स्वच्छ शौचालय, समुचित पुस्तकालय, नियमित कक्षाएं, सुसज्जित प्रयोगशालाएं तथा अन्य मूलभूत सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं हैं, तो फिर डेवलपमेंट शुल्क किस विकास के लिए लिया जा रहा है? सूरज सिंह ने यह भी कहा कि हाल के दिनों में विश्वविद्यालय एवं कई महाविद्यालयों द्वारा एक निजी कंपनी के माध्यम से अनिवार्य इंटर्नशिप के नाम पर प्रत्येक छात्र से अतिरिक्त शुल्क वसूले जाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। यदि किसी निजी संस्था को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से विद्यार्थियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाला जा रहा है, तो इसकी निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच कराई जानी चाहिए। उन्होंने मगध विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग की कि सभी संबद्ध महाविद्यालयों में प्रॉस्पेक्टस शुल्क, डेवलपमेंट शुल्क, प्रोसेसिंग शुल्क तथा इंटर्नशिप के नाम पर की जा रही अतिरिक्त वसूली पर तत्काल रोक लगाई जाए।

नौबतपुर में दर्दनाक हादसा: आहर में डूबने से दो सगे भाइयों की मौत

बीएनएम@ पटना। नौबतपुर थाने चेसी गांव में बुधवार को एक हृदय विदारक हादसे में पानी से भरे आहर में डूबने से दो नाबालिग सगे भाइयों की असमय मौत हो गई। इस घटना के बाद से ही परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। मृतकों की पहचान हुसैनचक गांव निवासी पिंटू सिंह के 14 वर्षीय पुत्र अभिजीत और 13 वर्षीय पुत्र प्रियांशु के रूप में हुई है।प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, क्षेत्र में धान रोपनी का काम चल रहा था। इसी दौरान छोटा भाई प्रियांशु खेत के पास बने आहर में नहाने चला गया। नहाते समय अचानक वह गहरे पानी में फिसल गया और डूबने लगा। अपने छोटे भाई को तड़पता देख बड़ा भाई अभिजीत उसे बचाने के लिए बिना सोचे-समझे आहर में कूद पड़ा। हालांकि, पानी गहरा होने के कारण दोनों भाई खुद को संभाल नहीं पाए और पानी में समा गए। घटना की भनक मिलते ही आसपास मौजूद ग्रामीणों ने तुरंत आहर में छलांग लगाई और काफी मशक्कत के बाद दोनों को बाहर निकाला। ग्रामीणों ने आनन-फानन में दोनों को नौबतपुर रेफरल अस्पताल पहुंचाया, जहां गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें पटना एम्स रेफर कर दिया। एम्स में इलाज के दौरान दोनों मासूमों ने दम तोड़ दिया। एक ही घर के दो चिरागों के इस तरह बुझ जाने से परिजनों में कोहराम मच गया है और पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है।

50 लीटर देसी शराब मामले का फरार अभियुक्त गिरफ्तार

बीएनएम@ समस्तीपुर। मोहनपुर थाना पुलिस ने शराब कारोबारियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत मंगलवार की देर रात कार्रवाई करते हुए एक फरार अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया।अपर थानाध्यक्ष विनय कुमार ने बताया कि थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव में विशेष छापेमारी अभियान चलाकर मध निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के थाना कांड संख्या-113/26 के नामजद अभियुक्त प्रमोद दास को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि पूर्व में पुलिस द्वारा की गई छापेमारी के दौरान प्रमोद दास के घर से 50 लीटर देसी शराब बरामद की गई थी। इस मामले में उसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी, लेकिन घटना के बाद से वह लगातार फरार चल रहा था। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास कर रही थी।थानाध्यक्ष विनय कुमार ने कहा कि शराब कारोबारियों, फरार अभियुक्तों एवं वारंटियों के विरुद्ध विशेष अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि अवैध शराब के निर्माण, भंडारण एवं कारोबार में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा तथा ऐसे लोगों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

जिले में बढ़ते बाल अपराध ने पुलिस की उड़ाई नींद

बीएनएम@ शेखपुरा। जिले में अपराध की दुनिया में नाबालिग बच्चों की बढ़ती भागीदारी ने पुलिस प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। हाल के कई गंभीर आपराधिक मामलों में नाबालिगों की संलिप्तता सामने आने के बाद पुलिस अब जागरूकता अभियान चलाने की तैयारी में है। विद्यालय में हथियार लेकर पहुंचे बच्चों की गिरफ्तारी से लेकर कसार थाना क्षेत्र के चर्चित डबल मर्डर तक, नाबालिगों की भूमिका ने लोगों को हैरान कर दिया है। रुपये के लेनदेन को लेकर हुए दोहरे हत्याकांड में भी नाबालिगों की संलिप्तता सामने आई थी। वहीं बरबीघा के चर्चित नींबू विक्रेता हत्याकांड में भी एक बच्चे की भूमिका सामने आई। इसके अलावा अरियरी, शेखपुरा और सिरारी थाना क्षेत्रों में बुलेट बाइक से किए गए लूटकांड में भी तीन नाबालिगों की संलिप्तता सामने आ चुकी है। लगातार सामने आ रहे इन मामलों ने पुलिस की नींद उड़ा दी है। SDPO डॉ. राकेश कुमार ने कहा कि जिले में सूखा नशा का बढ़ता प्रचलन, परिवार की अनदेखी और शिक्षण संस्थानों की लापरवाही इसके प्रमुख कारण हैं।

शेखपुरा में 6,258 नए राशन कार्ड बनाने के लक्ष्य पर चर्चा

बीएनएम@ शेखपुरा। जिले में राशन कार्ड से वंचित योग्य परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ने के लिए बुधवार, 22 जुलाई को टाउन हॉल में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अनुमंडल पदाधिकारी प्रियंका कुमारी ने की। बैठक में जिले में 6,258 नए राशन कार्ड बनाने के लक्ष्य को लेकर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ विस्तार से चर्चा की गई। एसडीओ प्रियंका कुमारी ने कहा कि सरकार की मंशा है कि कोई भी गरीब और पात्र परिवार राशन कार्ड के लाभ से वंचित न रहे। उन्होंने सभी योग्य लाभुकों से जल्द से जल्द ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने की अपील की, ताकि आवेदनों की जांच के बाद समयबद्ध तरीके से नए राशन कार्ड जारी किए जा सकें।

हरसिद्धि में खाद की खुली कालाबाजारी! अधिकारियों की चेतावनी बेअसर, यूरिया-डीएपी के नाम पर किसानों से मनमानी वसूली

हरसिद्धि/मोतिहारी@त्रिभुवन कुमार

खरीफ सीजन के बीच हरसिद्धि प्रखंड में खाद की कथित कालाबाजारी का मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है। किसानों का आरोप है कि प्रशासनिक निर्देशों और विभागीय अनुशंसाओं के बावजूद कई खाद विक्रेता निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत वसूल रहे हैं। इससे किसानों में भारी नाराजगी है। उनका कहना है कि शिकायतों के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जबकि जनप्रतिनिधियों की चुप्पी भी कई सवाल खड़े कर रही है। मानिकपुर, गायघाट, गोविन्दापुर, घीउवाढार, भादा, ओल्हा, मेहता टोला, मुरारपुर, जगापाकड़ और मुरारपुर सहित कई गांवों के किसानों का कहना है कि सरकारी निर्धारित दर पर यूरिया और डीएपी उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। किसानों का आरोप है कि यूरिया का एक बोरा 450 से 550 तक तथा डीएपी का एक बोरा 1,800 से 2,000 तक बेचा जा रहा है। धान की खेती के इस महत्वपूर्ण समय में खाद की मांग अधिक होने का लाभ उठाकर कुछ विक्रेता मनमानी वसूली कर रहे हैं, जिससे किसानों को मजबूरी में अधिक कीमत चुकानी पड़ रही है। किसानों का कहना है कि उन्होंने कई बार संबंधित अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन न तो नियमित छापेमारी की जा रही है और न ही अधिक कीमत वसूलने वाले दुकानदारों के विरुद्ध कोई ठोस कार्रवाई हो रही है। उनका आरोप है कि कार्रवाई के अभाव में कालाबाजारी करने वालों का मनोबल लगातार बढ़ता जा रहा है। किसानों का कहना है कि यदि समय रहते प्रशासन सख्ती दिखाता तो स्थिति इतनी गंभीर नहीं होती। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और कृषि विभाग से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने, दोषी खाद विक्रेताओं के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने, उनका लाइसेंस रद्द करने तथा सरकारी निर्धारित दर पर पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराने की मांग की है। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाने को विवश होंगे। इस संबंध में हरसिद्धि प्रखंड कृषि पदाधिकारी राघव प्रसाद का पक्ष जानने के लिए उनसे संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन समाचार लिखे जाने तक उनसे संपर्क नहीं हो सका।

पंचायत दिवस पर विशेष अभियानः ऑफलाइन माध्यम से जुड़ेंगे नए राशन कार्ड, पात्र परिवारों को मिलेगा लाभ

बीएनएम@ रामगढ़वा

क्षेत्र के पात्र एवं जरूरतमंद परिवारों को राशन कार्ड योजना का लाभ दिलाने के उद्देश्य से प्रशासन ने विशेष ऑफलाइन अभियान शुरू किया है। अभियान के तहत राशन कार्ड से वंचित पात्र परिवारों के नाम निर्धारित प्रपत्र 'क' के माध्यम से जोड़े जाएंगे, ताकि कोई भी योग्य परिवार सरकारी खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित न रह जाए। प्रशासन द्वारा अभियान को दो चरणों में संचालित किया जा रहा है। पहला चरण 20 जुलाई से 26 जुलाई तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण 26 जुलाई से 5 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। इस दौरान पंचायत स्तर पर आवेदन प्राप्त कर उनकी जांच की जाएगी और पात्र लाभुकों के नाम राशन कार्ड में जोड़ने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। एमओ रंजन कुमार ने बताया कि अभियान का उद्देश्य प्रत्येक पात्र परिवार को योजना का लाभ दिलाना है। उन्होंने संबंधित कर्मियों को निर्देश दिया है कि पंचायत दिवस पर प्राप्त सभी आवेदनों की निष्पक्ष एवं सूक्ष्म जांच कर समयबद्ध तरीके से कार्रवाई सुनिश्चित करें, ताकि योग्य लाभुकों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) सहित समाज के कमजोर एवं वंचित वर्गों के लोगों के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है, जिससे उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई न हो। प्रशासन ने क्षेत्र के नागरिकों से अपील की है कि वे निर्धारित अवधि के भीतर आवश्यक दस्तावेजों के साथ पंचायत स्तर पर आवेदन जमा कर इस विशेष अभियान का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।

सिविल सर्जन से दुर्व्यवहार के विरोध में पताही सीएचसी की ओपीडी रही ठप, इमरजेंसी सेवा जारी

बीएनएम@ पताही

अरवल में सिविल सर्जन के साथ हुए कथित दुर्व्यवहार की घटना के विरोध में मंगलवार को पताही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) के चिकित्सकों ने ओपीडी सेवा बंद रखी। विरोधस्वरूप पूरे दिन सामान्य मरीजों का इलाज नहीं हो सका, जबकि गंभीर एवं आपातकालीन मरीजों के लिए इमरजेंसी सेवा पूर्ववत संचालित होती रही। सीएचसी के चिकित्सा प्रभारी डॉ. शंकर बैठा ने बताया कि अरवल की घटना के विरोध में चिकित्सकों ने सांकेतिक रूप से ओपीडी सेवा स्थगित की है। उन्होंने कहा कि मरीजों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को देखते हुए इमरजेंसी सेवाओं को प्रभावित नहीं होने दिया गया तथा सभी गंभीर मरीजों का उपचार किया गया। सूत्रों के अनुसार, हाल के दिनों में पताही सीएचसी के चिकित्सकों के बीच सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ी है। कुछ दिन पहले हार्ट अटैक से पीड़ित एक वृद्ध की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। चिकित्सकों ने उसे बचाने का हरसंभव प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद मृतक के परिजनों एवं अन्य लोगों ने अस्पताल परिसर में हंगामा किया था। घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग की ओर से कई स्तरों पर जांच भी की गई। लगातार विवाद और जांच की प्रक्रिया के कारण चिकित्सकों के बीच मानसिक दबाव और असुरक्षा की भावना बनी हुई है। हालांकि, इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। मंगलवार को ओपीडी बंद रहने से इलाज के लिए पहुंचे कई मरीजों को बिना उपचार लौटना पड़ा। वहीं, इमरजेंसी वार्ड में चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों ने गंभीर मरीजों का उपचार जारी रखा। चिकित्सकों का कहना है कि मरीजों की सेवा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है, लेकिन सुरक्षित एवं सम्मानजनक कार्य वातावरण सुनिश्चित करना भी आवश्यक है।

ड्रोन तकनीक अपनाकर खेती को बनाएं लाभकारी, किसानों को दिया गया आधुनिक कृषि का प्रशिक्षण

बीएनएम@ सुगौली/मोतिहारी

कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों के बढ़ते उपयोग और किसानों को उन्नत खेती के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके), परसौनी द्वारा नयंश कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ), सुगौली के कार्यालय में "कृषि में ड्रोन का महत्व" विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को ड्रोन तकनीक की उपयोगिता, उसके व्यावहारिक प्रयोग तथा खेती में होने वाले लाभों की जानकारी देना था। प्रशिक्षण को संबोधित करते हुए कृषि अभियंत्रण विशेषज्ञ डॉ. अंशू गंगवार ने कहा कि वर्तमान समय में ड्रोन तकनीक कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ला रही है। इसके उपयोग से खेती की लागत कम होती है, समय और श्रम की बचत होती है तथा फसल उत्पादन के साथ-साथ गुणवत्ता में भी सुधार संभव है। उन्होंने किसानों से आधुनिक तकनीकों को अपनाकर खेती को अधिक लाभकारी, वैज्ञानिक और टिकाऊ बनाने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि ड्रोन के माध्यम से कीटनाशकों एवं तरल उर्वरकों का समान और सटीक छिड़काव किया जा सकता है। इससे रसायनों की खपत कम होती है, श्रम लागत घटती है और कम समय में अधिक क्षेत्र में प्रभावी छिड़काव संभव हो पाता है। साथ ही किसानों को खरपतवार प्रबंधन के लिए आर.ए.यू. व्हील हो, साइकिल हो, ग्रबर और कोनो वीडर जैसे आधुनिक कृषि यंत्रों की जानकारी देते हुए कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना करने की सलाह भी दी। कार्यक्रम के दौरान कृषि विज्ञान केंद्र, परसौनी के मृदा वैज्ञानिक डॉ. आशीष राय ने धान की फसल को खैरा रोग से बचाने तथा अधिक उत्पादन के लिए जिंक के संतुलित उपयोग की सलाह दी। उन्होंने किसानों से कहा कि खैरा रोग के लक्षण दिखाई देने का इंतजार न करें, बल्कि समय पर जिंक का प्रयोग कर फसल को सुरक्षित रखें, जिससे बेहतर उपज प्राप्त की जा सके। प्रशिक्षण में बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया और आधुनिक कृषि तकनीकों, विशेषकर ड्रोन आधारित खेती के बारे में जानकारी प्राप्त की। विशेषज्ञों ने किसानों के सवालों का जवाब देते हुए उन्हें वैज्ञानिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित किया।

शेखपुरा में कांग्रेस का प्रदर्शन, मोदी-शाह और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग

बीएनएम@ शेखपुरा

नई दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास का घेराव करने पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं के साथ पुलिस द्वारा कथित बदसलूकी तथा छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में शेखपुरा जिला कांग्रेस कमिटी ने बुधवार को जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व वरिष्ठ कांग्रेस नेता जितेंद्र नाथ ने किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन आजाद हिंद आश्रम से शुरू होकर चांदनी चौक तक पहुंचा। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह तथा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की मांग की। वरिष्ठ कांग्रेस नेता जितेंद्र नाथ ने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज दबाना और छात्रों पर बल प्रयोग करना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। प्रदर्शन में प्रखंड अध्यक्ष दीपक कुमार, संजय सिंह, प्रमोद यादव, आमिर महतो, गोरेलाल कुशवाहा, राहुल कुमार, राजेश रंजन उर्फ गुरु मुखिया, पप्पू राज मंडल, प्रेम कुमार गुप्ता समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे।

किरायेदारों का पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराया तो मकान मालिक भी जाएंगे जेल

बीएनएम@ शेखपुरा। जिले में बढ़ती आपराधिक घटनाओं के बीच पुलिस अब अपराधियों को पनाह देने वाले ठिकानों पर भी शिकंजा कसने की तैयारी में है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि बाहरी जिलों से आने वाले कई अपराधी शेखपुरा में किराये का मकान लेकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में अब पुलिस ने मकान मालिकों को कड़ी चेतावनी दी है। इस संबंध में एसडीपीओ डॉ. राकेश कुमार ने कहा कि जिले में घटित कई आपराधिक घटनाओं में बाहरी जिलों से आए अपराधियों की संलिप्तता सामने आ रही है। ये अपराधी किराये के मकान में रहकर स्थानीय स्तर पर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कोई भी मकान मालिक कमरा किराये पर देने से पहले किरायेदार का अनिवार्य रूप से पुलिस वेरिफिकेशन कराएं। एसडीपीओ ने चेतावनी दी कि यदि किसी मकान मालिक ने बिना पुलिस सत्यापन के किसी व्यक्ति को किराये पर रखा और बाद में वह किसी आपराधिक घटना में शामिल पाया गया, तो मकान मालिक की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। ऐसी स्थिति में अपराधी के साथ-साथ मकान मालिक पर भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है और उसे जेल जाना पड़ सकता है। दरअसल, हाल ही में बुलेट बाइक से लूटकांड में शामिल तीन अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद यह मामला सामने आया। गिरफ्तार अपराधियों में एक भागलपुर और दो नवादा जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार, तीनों शेखपुरा में किराये के मकान में रहकर लूट की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे।

अपराधियों के लिए 'सेफ हाउस' बन रहे किराये के मकानों पर पुलिस का शिकंजा

रक्सौल एयरपोर्ट निर्माण कार्य की डीएम ने की समीक्षा, लंबित भू-अर्जन भुगतान शीघ्र पूरा करने का निर्देश

बीएनएम@ मोतिहारी

जिला के रक्सौल एयरपोर्ट निर्माण कार्य को गति देने के उद्देश्य से जिलाधिकारी सौरभ सुमन यादव एवं पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने वरीय अधिकारियों के साथ एयरपोर्ट स्थल का निरीक्षण कर निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया। निरीक्षण के बाद रक्सौल परिसदन में आयोजित समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने लंबित भू-अर्जन मामलों का शीघ्र निष्पादन एवं रैयतों को जल्द भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि जिन रैयतों का भुगतान अब तक नहीं हो सका है, उनके एलपीसी एवं भूमि संबंधी अभिलेख एक सप्ताह के भीतर अंचल अधिकारी, रक्सौल द्वारा जिला भू-अर्जन कार्यालय को उपलब्ध कराए जाएं। उन्होंने जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को प्राप्त अभिलेखों की नियमित समीक्षा कर भुगतान प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया। समीक्षा बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी, रक्सौल को अंचल अधिकारी के साथ नियमित समीक्षा करते हुए शेष रैयतों के अभिलेख शीघ्र जिला भू-अर्जन कार्यालय भेजने का निर्देश दिया गया, ताकि एयरपोर्ट परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी हो सके।निरीक्षण एवं समीक्षा के दौरान उप विकास आयुक्त डॉ. प्रदीप कुमार, सदर अनुमंडल पदाधिकारी मोतिहारी, अनुमंडल पदाधिकारी रक्सौल, अंचल अधिकारी रक्सौल सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

संसद या सियासी अखाड़ा?

विचारधारा, नीति, कार्यक्रम, चुनाव घोषणापत्र आदि का आज क्या औचित्य रह गया है? अगर ये राजनीति के प्रेरक तत्व ना रहें, तो फिर पहलवानी के अखाड़े और संसद के बीच क्या फर्क रह जाएगा? मानसून सत्र की शुरुआत के साथ संसद का नज़ारा कुछ बदला नजर आएगा। यह संभवतः पहला मौका है, जब बिना चुनाव हुए सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के संख्या बल में गुणात्मक बदलाव हुआ दिखेगा। बजट सत्र के बाद तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना (उद्धव) बड़ी टूट-फूट हो चुकी है, जबकि एनसीपी (शरद पवार गुट) के रुख में बदलाव के संकेत मिले हैं। इससे बिना नया जनादेश आए ही सत्ताधारी एनडीए मजबूत हो गया है। इस हद तक कि अभी दो महीने पहले लोकसभा सीटों के परिसीमन के मकसद से लाया गया जो विधेयक गिर गया था, सत्ता पक्ष उसे फिर से लाने की तैयारी में दिखा है। इसी तरह विवादास्पद विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक-2025 और गिरफ्तारी होने पर 30 दिन के अंदर मुख्यमंत्री/ मंत्री पद खत्म करने का प्रावधान करने वाले विधेयक को भी लाने की चर्चा थी (जिसका इरादा शायद टाल दिया है)। पिछले सत्र तक इन विधेयकों के पारित होने की संभावना बेहद कमजोर थी। अभी भी इनके लिए सरकार संख्या बल का पूरा इंतजाम नहीं कर पाई है, लेकिन कुछ और जोड़-तोड़ में कामयाब रही, तो इनके पारित होने की संभावना बन सकती है। मगर यही समस्या है। वह संभावना 2024 में आए जनादेश की भावना के विपरीत होगी। मुद्दा है कि दांव-पेच से जनादेश की भावना को इस तरह धता बताने के चलन आम हो जाता है, तो फिर विचारधारा, नीति, कार्यक्रम, चुनाव घोषणापत्र आदि का क्या औचित्य रह जाएगा? ये राजनीति के प्रेरक तत्व ना रहें, तो फिर पहलवानी के अखाड़े में होने वाली जोर-आजमाईश और संसदीय प्रक्रियाओं के बीच क्या फर्क रहेगा? क्या उसके बाद भी संसद को बहस के जरिए अधिकतम संभव सहमति निर्माण का मंच माना जा सकेगा? दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत में इन प्रश्नों के उत्तर लगातार नकारात्मक होते गए हैं। संसद शोर, हंगामे, वॉकआउट, बहिष्कार, और कई बार तो शारीरिक बल के जरिए झड़पों का स्थल बनती चली गई है। नतीजतन, अधिवेशनों से पहले गंभीर बहस से ज्यादा अपेक्षा टकराव और तू तू-मैं- मैं की रहने लगी है। मानसून सत्र के पहले भी राजनीतिक क्षितिज पर यही माहौल हावी नजर आया है।

भारत में खो गई है जवाबदेही?

श्रुति व्यास

शनिवार को सोनम वांगचुक के साथ जो हुआ, उसे देखते हुए पहली बार लगा कि भारत में केवल राजनीति नहीं बदली है, जवाबदेही भी बदल गई है।

1975 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति जगमोहनलाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी को चुनावी अनियमितताओं का दोषी ठहराते हुए उनका चुनाव खारिज किया था। फैसला सीधे प्रधानमंत्री के खिलाफ था। इंदिरा गांधी ने उसे स्वीकार करने के बजाय आपातकाल लगाया। वह लोकतंत्र का सबसे अंधकारमय अध्याय था, लेकिन उसमें एक राजनीतिक सच्चाई भी थी। आरोप प्रधानमंत्री पर था और पूरा देश जानता था कि जिम्मेदारी भी प्रधानमंत्री की है। सत्ता बचाने का उनका तरीका लोकतांत्रिक नहीं था, लेकिन जवाबदेही का अंतिम पता किसी को खोजने की जरूरत नहीं थी। भारतका हर नागरिक जानता-समझता था

चौदह वर्ष बाद यही कसौटी राजीव गांधी के सामने आई। वे "मिस्टर क्लीन" की छवि लेकर सत्ता में आए, लेकिन बोफोर्स विवाद उनकी पूरी राजनीतिक पहचान पर छा गया। हालांकि अदालत कभी यह साबित नहीं कर सकी कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से रिश्वत ली थी। फिर भी जनता ने राजनीतिक फैसला दे दिया। प्रधानमंत्री के इतने निकट हुआ सौदा प्रधानमंत्री की राजनीतिक जिम्मेदारी भी बना। और1989 में उसकी कीमत उन्हें सत्ता गंवाकर चुकानी पड़ी। फिर मनमोहन सिंह आए। उनकी व्यक्तिगत ईमानदारी पर शायद ही किसी ने सवाल उठाया हो। लेकिन लोकतंत्र व्यक्ति की नहीं, पद की जवाबदेही भी तय करता है। 2जी स्पेक्ट्रम और कोयला आवंटन विवाद उनके कार्यकाल में सामने आए। लंबे समय तक कोयला मंत्रालय स्वयं उनके पास था। इसलिए "मुझे जानकारी नहीं थी" जैसी सफाई राजनीतिक रूप से टिक नहीं सकी। किसी ने यह नहीं कहा कि उन्होंने अपनी जेब भरी, लेकिन इतना पर्याप्त था कि विवाद प्रधानमंत्री कार्यालय की चौखट तक पहुँच चुका था। 2014 में उसकी राजनीतिक कीमत कांग्रेस ने चुकाई। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और मनमोहन सिंह— तीनों एक-दूसरे से बिल्कुल अलग थे। फिर भी उनमें एक समानता थी। उनके आसपास पैदा हुआ बड़ा विवाद अंततः प्रधानमंत्री तक पहुँचता था। कभी प्रतिष्ठा जाती थी, कभी सरकार, कभी दोनों। उस समय जवाबदेही को सत्ता के शिखर (प्रधानमंत्री पद) तक पहुँचने में ज्यादा समय नहीं लगता था। यही भारतीय लोकतंत्र का विकास था। उपलब्धि थी। एक महत्वपूर्ण राजनीतिक आदत थी। लोकतंत्र में सरकार का चेहरा ही उसकी अंतिम जवाबदेही भी होता था। यहीं मुझे लगता है कि पिछले दशक में सबसे बड़ा बदलाव आया है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का दशक विवादों से खाली नहीं रहा। किसानों का लंबा आंदोलन हुआ। देश की शीर्ष महिला पहलवानों ने सत्तारूढ़ दल के प्रभावशाली सांसद के खिलाफ संघर्ष किया। प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नपत्र बार-बार लीक हुए। भर्ती प्रक्रियाएँ संदेह के घेरे में आईं। लद्दाख में असंतोष बना। कई मौकों पर नागरिकों ने सरकार से जवाब माँगा। लेकिन इन सबमें एक बात समान रही। विवाद जंतर-मंतर, दिल्ली के प्रवेश दरवाजों तक और सरकार तक भी पहुँचे, मगर प्रधानमंत्री तक नहीं। यही इस दौर की सबसे असाधारण राजनीतिक विशेषता है। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि विरोध करने वाले वही वर्ग थे जिन्हें नरेंद्र मोदी ने अपनी राजनीति के केंद्र में रखा था। अच्छे दिनों के वायदे में किसान राष्ट्र की रीढ़ बताए गए थे। युवाओं को भारत की सबसे बड़ी शक्ति कहा गया। "डेमोग्राफिक डिविडेंड" केवल आर्थिक अवधारणा नहीं, बल्कि पूरे शासनकाल की राजनीतिक कथा थी। 2018 में तुमकुरु के एक युवा सम्मेलन में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यदि समाज के लिए "विद्यार्थी देवो भव" मंत्र है, तो उनके लिए "युवा शक्ति देवो भव" मंत्र है।

फिर प्रश्नपत्र लीक का दौर आया। करोड़ों युवाओं ने केवल परीक्षाएँ नहीं खोईं; उन्होंने व्यवस्था पर अपना भरोसा भी खोया। स्वाभाविक अपेक्षा थी कि जिसने युवाओं को अपनी सबसे बड़ी शक्ति बताया, वही उनके सबसे कठिन समय में सबसे पहले दिखाई देगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहले सन्नाटा रहा। फिर प्रतीक्षा। फिर वही मंत्री अपने पद पर बने रहे जिनके विभाग पर सवाल उठ रहे थे। धीरे-धीरे शिकायत से अधिक चर्चा शिकायत करने वालों पर होने लगी। भारतीय राजनीति में यह नई रणनीति नहीं है। जब किसी प्रश्न का उत्तर कठिन हो, तो बहस को प्रश्न से हटाकर विरोध पर ले जाइए। धीरे-धीरे मूल प्रश्न ही धुँधला पड़ जाता है। यही बात दूसरे विवादों में भी दिखाई देती है। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ देश की सात शीर्ष महिला पहलवानों ने आरोप लगाए। लखीमपुर खीरी में चार किसानों की मौत के बाद भी केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी लंबे समय तक पद पर बने रहे। राष्ट्रीय परीक्षा विवाद में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर सवाल उठे। हर बार राजनीतिक बहस किसी मंत्री, किसी सांसद या किसी संस्था तक पहुँची, लेकिन शायद ही कभी प्रधानमंत्री तक पहुँची। पहले ऐसा नहीं होता था। इनमें से हर विवाद प्रधानमंत्री कार्यालय के इतना निकट था कि भारतीय राजनीति के पहले के दौर में वह एक-दो सीढ़ियाँ और ऊपर चढ़ता। अब वह जैसे अंतिम सीढ़ी पर पहुँचने से पहले ही रुक जाता है। ऐसा क्यों? इसका एक उत्तर राजनीतिक प्रबंधन में है। हर सरकार विवादों को नियंत्रित करने की कोशिश करती है। जाँच बैठती है, समय लिया जाता है, बहस का केंद्र बदला जाता है। मोदी सरकार ने यह कला असाधारण दक्षता से सीखी है। लेकिन केवल राजनीतिक प्रबंधन पर्याप्त उत्तर नहीं है। उसके लिए नरेंद्र मोदी की सार्वजनिक छवि को भी समझना होगा। उनके पीछे कोई राजनीतिक वंश नहीं है। रिश्तेदारों के लाभ उठाने की सार्वजनिक कहानियाँ नहीं हैं। निजी संपत्ति बढ़ाने की व्यापक धारणा भी नहीं है। उन्होंने स्वयं को बार-बार "फकीर" कहा है। बड़ी संख्या में लोग इस छवि पर विश्वास करते हैं। और लोकतंत्र में विश्वास केवल नेता की छवि नहीं बदलता, जवाबदेही का रास्ता भी बदल देता है। फिर भी यहीं सबसे बड़ा विरोधाभास खड़ा होता है। यदि प्रधानमंत्री वास्तव में अपने आसपास के विवादों से पूरी तरह अछूते हैं, तो फिर वही विवाद बार-बार बने क्यों रहते हैं? जो नेता व्यक्तिगत रूप से सबसे सुरक्षित हो, उसके लिए विवादित सहयोगियों से दूरी बनाना, उन्हें हटाना सबसे आसान होना चाहिए। वास्तविक अधिकार वही है जो अपने लोगों पर भी लागू हो सके। लेकिन बार-बार उलटा दिखाई देता है। विवाद समाप्त करने के बजाय उन्हें साथ लेकर चलने का निर्णय लिया जाता है। संभव है इसका उत्तर नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत निष्कलंकता से कम और उनकी तथा अमित शाह की राजनीतिक गणित से अधिक जुड़ा हो। हर नेता निष्ठाओं के नेटवर्क के सहारे शासन करता है। किसी प्रभावशाली सहयोगी को हटाना केवल नैतिक निर्णय नहीं, राजनीतिक जोखिम भी है। शक्ति-संतुलन बदलता है, संगठन को संदेश जाता है और समीकरण प्रभावित होते हैं। इसलिए विवाद को सह लेना, कई बार उसे समाप्त करने से सस्ता पड़ता है। या फिर बात इससे भी आगे की है। संभव है नेतृत्व को अब यह भरोसा हो गया हो कि विवाद, आंदोलन, असंतोष, गुस्सा शीर्ष नेतृत्व तक राजनीतिक नुकसान पहुँचाने की क्षमता खो चुके हैं। नरेंद्र मोदी और उनके समर्थकों के बीच बना भावनात्मक संबंध इतना मजबूत हो चुका है कि बड़ी संख्या में मतदाता प्रधानमंत्री और उनके नाम पर शासन करने वालों के बीच स्पष्ट अंतर कर लेते हैं। सरकार से शिकायत हो सकती है, किसी मंत्री से नाराज़गी भी हो सकती है, लेकिन उसकी राजनीतिक जिम्मेदारी स्वतः प्रधानमंत्री तक नहीं पहुँचती। यहीं से वह प्रश्न जन्म लेता है जो शायद नरेंद्र मोदी से भी बड़ा है। लोकतंत्र का तब क्या होता है, जब जवाबदेही अपनी पूरी यात्रा करना बंद कर दे? स्वतंत्र भारत के अधिकांश इतिहास में राजनीतिक जिम्मेदारी अंततः सत्ता के सर्वोच्च पद तक पहुँच जाती थी। कभी यह प्रक्रिया अपूर्ण थी, कभी कठोर, कभी अन्यायपूर्ण भी। लेकिन यात्रा पूरी होती थी। आज असहमति अब भी है। आंदोलन भी हैं। सवाल भी हैं। बदला है तो केवल उनका रास्ता। शनिवार को सोनम वांगचुक के साथ जो हुआ, उसने मुझे इसी बदलाव का एहसास कराया। प्रश्न उठा, लेकिन वह भी अंततः उसी जगह जाकर ठहर गया जहाँ पिछले कई वर्षों से दूसरे प्रश्न ठहरते आए हैं। शायद यही हमारे समय का सबसे बड़ा राजनीतिक परिवर्तन है। भारत में विवाद खत्म नहीं हुए हैं। विरोध भी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन जवाबदेही जैसे अपनी आख़िरी सीढ़ी तक पहुँचना भूल गई है। यह केवल एक लोकप्रिय प्रधानमंत्री की कहानी नहीं है। यह उस लोकतांत्रिक मनोविज्ञान की कहानी है जिसमें सत्ता का सर्वोच्च पद पहले की तरह सबसे बड़ा उत्तरदायित्व नहीं रह गया। कभी भारतीय लोकतंत्र में जवाबदेही का रास्ता सीधा प्रधानमंत्री के दरवाज़े तक जाता था। आज वह रास्ता जैसे कहीं बीच में मुड़ जाता है। शायद यही कारण है कि मोदी वर्षों की कहानी केवल नरेंद्र मोदी की कहानी नहीं रह जाती। वह भारतीय लोकतंत्र की बदलती प्रकृति की कहानी बन जाती है। उसमें असहमति जीवित है, प्रश्न भी जीवित हैं, लेकिन उन प्रश्नों का अंतिम पता अब पहले जितना निश्चित नहीं रह गया है।

हिंदू राष्ट्र क्यों वांगचुक जैसे 'कॉकरोच' की सुने?

हरिशंकर व्यास

बेचारे सोनम वांगचुक! सांस मोदी के हिंदू राष्ट्र में ले रहे हैं बावजूद इसके माने बैठे हैं कि 'जनमत को जागरूक करना और सत्ता में बैठे लोगों को समझाना, एक ही सिक्के के दो पहलू हैंÓ। बारह वर्षों के अनुभवों में वांगचुक इतना भी नहीं समझ पाए कि मौजूदा हिंदू राष्ट्र के सिक्के के दो पहलू नहीं हैं। उसे इधर पलटिए या उधर, दोनों तरफ एक ही चेहरा है- नरेंद्र मोदी का। वही भक्तों के कलियुगी भगवान है। तभी हिंदू मानस में भगवान से जवाब-तलब नहीं होता, केवल पूजा, दर्शन और भक्ति होती है। तो कौन सा जनमत, कैसी जागरूकता और कैसी जवाबदेही?

इस सत्य का सबूत हजार साला गुलामी भी है। राम मंदिर टूटा, आक्रमण हुए, अपमान और पराधीनता का लंबा दौर बीता, लेकिन बहुसंख्यक हिंदू समाज ने कभी अपने आराध्य से यह प्रश्न नहीं किया कि 'आपके रहते यह सब क्यों हुआÓ? न ही उसके भीतर. दिमाग में यह आत्ममंथन बना कि हम हर संकट का समाधान स्वयं बनने के बजाय किसी भगवान, किसी अवतार, किसी उद्धारकर्ता की प्रतीक्षा में क्यों बैठे रहते हैं?

इक्कीसवीं सदी के कथित हिंदू राष्ट्र का भी यही सत्य है। हिंदू अब नागरिक नहीं भीड़ और भक्त में कनवर्ट है। इसलिए क्योंकि नागरिक सवाल पूछता है, जवाबदेही मांगता है। वह सत्ता को अपने प्रति उत्तरदायी मानता है। जबकि भक्त प्रश्न नहीं करता; वह आस्था में जीता है और मोदी के हर निर्णय को भगवान की लीला माने रहता है।

इसलिए सोचें, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सौ सालों के चाल, चेहरे, चरित्र ने हिंदुओं को कैसा 'अवतारÓ दिया? सदियों से किसी उद्धारकर्ता की प्रतीक्षा करते समाज के सामने अंततः नरेंद्र मोदी ऐसे स्थापित हुए कि वे या तो भगवान हैं, या मोदी ही भारत और भारत ही मोदी है। मोदी के हिंदू राष्ट्र में उन्ही की, अकेली की एक केंद्रित सत्ता है, जिसके सामने राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल, संसद और भाजपा जैसी राजनीतिक पार्टी सभी गौण है। मोहन भागवत हों या अमित शाह, राजनाथ सिंह हों या नितिन गडकरी; चुनाव

आयोग हो, न्यायपालिका हो, मीडिया हो या नौकरशाही- सत्ता का पूरा तंत्र मोदी के रचित तीर्थ (दिल्ली में बने नए प्रधानमंत्री महल, नई दफ्तरी इमारतों, कथित तीर्थ) की परिक्रमा करता होता है। कृपा, वैधता, प्रतिष्ठा और राजनीतिक भविष्य सभी का मालिक एक अकेले नरेंद्र मोदी। वैसे कलियुगी हिंदू इसी लायक है भी। आखिर हम मानते भी है कि जैसी प्रजा वैसा राजा। तब भला आज की दैवीय व्यवस्था में लोकतंत्र, जनमत, जागरूकता और जवाबदेही जैसे शब्दों का मूल्य कौड़ी भर भी होगा? कतई नहीं। नागरिक की जगह अब भक्त है और संस्थाओं की जगह व्यक्ति पूजा है तो सत्ता से प्रश्न पूछना या जवाबदेही की उम्मीद करना बेवकूफी वाली बातें हैं। ध्यान है पर्यावरणविद् और पूर्व आईआईटी प्रोफेसर जीडी अग्रवाल का नाम। बेचारे ने संन्यास लेकर स्वामी ज्ञानस्वरूप सानंद का नाम धारा और गंगा को अविरल-निर्मल रखने की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे। 111 दिनों तक जीवन दांव पर लगाने के बाद 11 अक्टूबर 2018 को ऋषिकेश के एम्स में दम तोड़ा। याद करें उनके निधन पर मोदी और उनकी सत्ता, संघ, भाजपा, साधु-संत, गंगा भक्तों. जनमत में किसी के भी आंसू नहीं निकले! इसलिए दिल्ली के जंतर-मंतर पर 20-21 दिनों से अनशन कर रहे सोनम वांगचुक का हिंदू राष्ट्र में जीरो अर्थ है। वे हिंदू अभिभावकों के बच्चों, देश की नई पीढ़ी के भविष्य के ठगी करने वाली नीट परीक्षा जैसी व्यवस्थाओं के खिलाफ कितना ही आंदोलन कर ले उनके लिए हिंदुओं की भीड़ नहीं जुटनी है। जो जुटी है या जुट रही है वह पहले से ही कॉकरोच का तमगा पाए हुए है। उन्हें चप्पल मार कर दबाया जाता है। कर्नाटक के एक अभिनेता प्रकाश राज ने जंतर मंतर जा कर बोला कि यह लड़ाई युवा छात्रों और देश के भविष्य की है व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए है। पर युवा छात्रों की भीड़ भी जब जंतर-मंतर नहीं पहुंची तो किसके लिए कौन सी लड़ाई? जाहिर है भगवान और भक्तों के नए भारत में लड़ाई संभव नहीं है। पिछले बारह वर्षों में बार-बार उभरे पैटर्न पर गौर करें। क्या हुआ है? न देखो, न सुनो, न जवाब दो और बस दर्शन, प्रवचन और चौबीसों घंटे झूठ बोलो। चुनाव जीतने की लीला को झूठ-फरेब से पकाते जाओ। लोकतंत्र, मर्यादा, असहमति की तमाम बाते भाड़ में। गंगा बचाने का अनशन हो या छात्रों, किसानों के साथ खिलवाड़ में आंदोलन हो पहले तो अनदेखी करो। बात ज्यादा बढ़े तो उसे बदनाम करो। फिर उसे किसी राजनीतिक साजिश, विदेशी एजेंडा, खालिस्तानी, अर्बन नक्सल, टुकड़े-टुकड़े गैंग या विपक्ष, कॉकरोचों के खाते में डाल दो। ऐसा किसान आंदोलन के समय हुआ तो अब परीक्षाओं में धांधली के वाकिये में भी है। किसान, पहलवान, मणिपुर की पीड़ित महिलाएं, प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थी छात्र और वांगचुक के मौजूदा मसले सब हिंदू राष्ट्र में वैसे ही हैंडल होते हुए है जैसे हिंदुओं की गुलामी के हजार सालों में हुआ। तब अंग्रेज हाकिमों का राजकाज तथा व्यवहार गुलाम प्रजा की रियलिटी में बना हुआ था। इक्कीसवीं सदी के हिंदू राष्ट्र में राजकाज भगवा और भक्त के उन रिश्तों में है, जिसमें सत्ता से प्रश्न राष्ट्रद्रोह है, हिंदूद्रोह है। इसलिए वांगचुक को या तो अनशन खत्म करना होगा या मरना होग। वैसे ही जैसे एक गंगा भक्त जीडी अग्रवाल ने 2018 में दम तोड़ा था।

मेष राशिः काफी समय से रुके हुए काम आज थोड़े ही प्रयास में में पूरे हो जाएंगे। जो लोग टूर एंड ट्रेवल का बिजनेस कर रहे हैं, उन्हें आज उम्मीद से अधिक फायदा होगा। आप नया वाहन खरीदने के लिये जीवनसाथी से सलाह ले सकते हैं। माता-पिता के साथ किसी तीर्थस्थल पर जाने का योग बन रहा है। बच्चे आज आउट डोर गेम खेलने की लिए जिद्द करेंगे साथ ही उनकी गतिविधि पर नजर बनाए रखें।

वृष राशि : आज का आपके लिए दिन खास रहने वाला है। जो शिक्षक हैं, वो आज छात्रों को कुछ नया सिखायेंगे। आज घर में किसी दूर के रिश्तेदार के आने की संभावना बन रही है। आज शाम का समय परिवार के साथ बीतेगा और नई टेक्नोलाजी से अपडेट होने का प्रयास करेंगे। जो लोग स्वीट्स ,कैफे आदि के बिजनेस से जुड़े हैं, उनको अच्छा मुनाफा होगा।

मिथुन राशि : आज का दिन आपके लिये ठीक-ठाक रहेगा। आपको खुद पर ध्यान देने की जरूरत है, आज अपने गुस्से पर काबू रखें, वरना आपके काम बिगड़ सकते हैं। साझेदारी में व्यवसाय कर रहे लोगों को उनके सहयोगी और कर्मचारियों के पूर्ण सहयोग से आज व्यावसायिक गतिविधियों को और अधिक बेहतर

कर्क राशि : आज का दिन आपके लिए मिली जुली प्रतिक्रिया देने वाला वाला रहेगा। कर्क लग्न और राशि वालों आपका पूरा दिन भाग-दौड़ में बीतेगा। आज के दिन आयात-निर्यात संबंधी व्यवसाय में अच्छा लाभ होने की स्थिति बन रही है। पेपर वर्क पूरा न होने से जरूरी काम बनते-बनते रुक सकता है।

सिंह राशि : आज का दिन आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। आज अपना कॉन्फिडेंस कम न होने दें, मन लगाकर काम करें। प्रॉपर्टी से संबंधित रुका हुआ मामला आपसी सहमति से आज हल हो सकता है। आज जो लोग कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं, नौकरी कर रहे लोग अपने स्थानांतरण संबंधी कार्यों के लिए आज अपने उच्च अधिकारियों से विचार-विमर्श अवश्य करें।

कन्या राशि : आज का दिन बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। आज अपनी दैनिक गतिविधियों में कुछ नयापन लाने का प्रयास करेंगे। पुरानी समस्याओं से आज राहत मिलेगी। इस समय अतिरिक्त आय प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। नए बिजनेस में निवेश करने का विचार बना सकते हैं। जहां जरूरत लगे, वहां समझौता करने के लिए तैयार रहेंगे।

तुला राशि : आज का दिन सामान्य रहने वाला है। काम को लेकर किसी तरह का डर मन में न रखें। कार्यस्थल पर अपने काम के प्रति सतर्क रहें कुछ लोग आज आपके विरुद्ध प्लानिंग कर सकते हैं, आपको ऐसे लोगों से थोड़ा संभलकर रहना होगा। रुके हुए पैसों की वापसी आज संभव है। बातचीत करके आप अपना काम निकालने में सक्षम रहेंगे।

वृश्चिक राशि : आज आपका का दिन उत्साह से भरा रहेगा। परिवार के किसी खास व्यक्ति के बारे में आपको कुछ रोचक बात पता चल सकती है और आज कुछ विशेष बातें सीखने को मिलेगी, जिससे आपका मनोबल बढ़ेगा। आज आप ज्यादातर काम आसानी से निपटाने में सफल रहेंगे।

धनु राशि : आज का दिन आपके जीवन में नई खुशियां लेकर आया है। आज आपकी सोच और प्लानिंग स्पष्ट रहेगी। आज आपकी कल्पना शक्ति का विस्तार होगा। आपकी कार्यकुशलता से उम्मीद के अनुरूप लाभ होगा। परिवार के साथ धार्मिक यात्रा का प्रोग्राम बनेगा। आज पारिवारिक मामलों में बड़ा फैसला ले सकते हैं।जो लोग बिजनेसमैन है।

मकर राशि : आज का दिन आपके लिए बेहतर रहेगा। आज आपकी कार्यप्रणाली में नयापन देखने को मिलेगा। इस राशि के जो लोग लेखन के क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं उनके लिए आज अपनी प्रतिभा को निखारने का दिन है। आज किसी से बेवजह की बातें न करें, जितना हो सके विवाद से दूर रहें।

कुंभ राशि : आज किस्मत आपका पूरा साथ देगी। आज आपकी इनकम बढ़ने के योग बन रहे हैं। आज आपको किसी नये बिजनेस में साझेदारी का प्रस्ताव मिल सकता है, इसका आपको आने वाले दिनों में काफी फायदा होगा। आज कुछ अनुभवी लोगों से मुलाकात का अवसर मिलेगा और आपको कई तरह के अनुभव मिलेंगे।

मीन राशि : आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा। आज बिजनेस में नये एग्रीमेंट होने की संभावना है। आज कार्यक्षेत्र में आप जो काम करेंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी। अपनी व्यवसायिक कार्यप्रणाली को आज दूसरों के समक्ष उजागर न करें। कई दिनों से घर में चल रही समस्या आज सुलझ जाएगी।

संसद का मानसून सत्र 2026 शुरू-विपक्ष का हंगामा शुरू

किशन सनमुखदास भावनानी

वैश्विक स्तरपर 20 जुलाई 2026 से प्रारंभ हुआ 13 अगस्त तक चलने वाले इस संसद क़े मानसून सत्र पर पूरे विश्व की नज़रें लगी हुई है।कुल 19 बैठकें निर्धारित हैं।संसद में 28 विधेयक लंबित हैं।इनमें से 5 नए विधेयक पेश किए जाने हैं और 2 लंबित विधेयकों को पारित कराने के लिए सूचीबद्ध किया गया है।यह केवल एक नियमित संसदीय सत्र नहीं,बल्कि भारत की राजनीति, अर्थव्यवस्था निवेश वातावरण और वैश्विक छवि के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा माना जा रहा है। यह सत्र ऐसे समय शुरू हुआ है जब भारत दुनियाँ की सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है,भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता लागू हो चुका है,अंतरराष्ट्रीय निवेशकों की निगाह भारत पर है और विकसित भारत -2047 का रोडमैप निर्णायक चरण में प्रवेश कर रहा है। मैं एडवोकेट किशन षणमुख दास भावना ने गोंदिया महाराष्ट्र अपने विचार इस आर्टिकल के माध्यम से प्रकट कर रहा हूं क़ि ऐसे समय संसद में होने वाली प्रत्येक बहस, प्रत्येक विधेयक और प्रत्येक राजनीतिक टकराव का प्रभाव केवल नई दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगा,बल्कि वैश्विक निवेशकों,अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों और भारतीय शेयर बाजार पर भी दिखाई देगा।सत्र प्रारंभ होने से पहले माननीय पीएम ने संसद परिसर में मीडिया को संबोधित करते हुए सभी दलों से रचनात्मक सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि संसद का उत्पादक संचालन देशहित,जनकल्याण और विकास के लिए आवश्यक है तथा भारत की हाल की उपलब्धियों को आगे बढ़ाने के लिए सार्थक चर्चा होनी चाहिए। दूसरी ओर विपक्ष पहले से ही सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की रणनीति बनाकर आया था, जिससे पहले दिन से ही टकराव की स्थिति बन गई। साथियों, सरकार ने इस मानसून सत्र के लिए लगभग आठ प्रमुख विधेयकों का विधायी एजेंडा रखा है। इनमें इन्कम-टैक्स (अमेन्डमेंट) बिल,2026,जिसमें विदेशी संस्थागत निवेशकों और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स को सरकारी प्रतिभूतियों से होने वाली आय पर कर छूट से संबंधित प्रावधान।माइक्रो , स्माल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट (अमेन्डमेंट) बिल 2026 एमएसएमई को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने की व्यवस्था मजबूत करना।मध्यस्थता (आरबिस्ट्रेशन) के निर्णयों के प्रभावी क्रियान्वयन का प्रावधान।राज्यों को फेसिलिटेशन कौंसिल के गठन में अधिक अधिकार देना। रजिस्ट्रेशन ऑफ़ बर्थस एंड डेथस (अमेन्डमेंट) बिल ,2026जन्म और मृत्यु के विलंबित पंजीकरण के नियमों को अधिक कठोर बनाना। पंजीकरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनाना।सुप्रीम कोर्ट (नंबर ऑफ़ जजेस) अमेन्डमेंट बिल, 2026 सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने का प्रस्ताव। प्रेवेंशन ऑफ़ इंसल्ट्स टू नेशनल हॉनर (अमेन्डमेंट) बिल, 2026राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम, 1971 में संशोधन। रिपोर्टों के अनुसार इसमें वंदे मातरम् को वैधानिक संरक्षण देने और उसके अपमान को दंडनीय बनाने का प्रावधान शामिल है। इसके अलावापहले से लंबित प्रमुख कई विधेयक शामिल हैं। इसके अतिरिक्त राजनीतिक गलियारों में परिसीमन (डेलिमिटेशन) से जुड़े संभावित विधेयक पर भी व्यापक चर्चा रही,क्योंकि इसका संबंध भविष्य में महिलाओं के आरक्षण के प्रभावी क्रियान्वयन और लोकसभा सीटों के पुनर्निर्धारण से जोड़ा जा रहा है। हालांकि सरकार ने परिसीमन पर अंतिम निर्णय सार्वजनिक रूप से स्पष्ट नहीं किया,फिर भी यह विषय पूरे सत्र का सटीकता से सबसे संवेदनशील राजनीतिक मुद्दा बन गया। साथियों,उधर विपक्ष ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि वह सरकार को केवल विधेयकों पर नहीं,बल्कि महंगाई, बेरोजगारी,कृषि संकट, मणिपुर की स्थिति,नीट परीक्षा विवाद,छात्र आंदोलनों अयोध्या मंदिर दान प्रकरण तथा परिसीमन जैसे विषयों पर घेरेगा। विपक्ष का तर्क था कि जनता से जुड़े इन प्रश्नों पर पहले चर्चा होनी चाहिए, जबकि सरकार का जोर विधायी कार्यों को आगे बढ़ाने पर था। यही टकराव पहले दिन काम काज़ शुरू होने के पहले घंटे से ही सदन के भीतर खुलकर दिखाई दिया। 20 जुलाई की सुबह जैसे ही लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई,विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्ष ने छात्र आंदोलनों और परीक्षा संबंधी मुद्दों पर तत्काल चर्चा की मांग की।अध्यक्ष द्वारा बार-बार व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई,किंतु शोर- शराबा जारी रहा। परिणामस्वरूप दोनों सदनों की कार्यवाही बार-बार स्थगित करनी पड़ी। समाचारों के अनुसार दोपहर तक लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही कम से कम पाँच बार स्थगित हुई और बाद में दोनों सदनों को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। पहले दिन कोई बड़ा विधायी कार्य नहीं हो सका। साथियों, पहले दिन की घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया कि आगामी 25 दिन सरकार और विपक्ष के बीच तीखी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी। सरकार का लक्ष्य आर्थिक सुधारों,कर प्रणाली, उद्योग,निवेश और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े विधेयकों को पारित कराना है, जबकि विपक्ष जनहित से जुड़े मुद्दों पर सरकार को जवाबदेह बनाने की रणनीति अपनाए हुए है। यदि दोनों पक्षों के बीच संवाद स्थापित नहीं होता, तो संसदीय उत्पादकता प्रभावित हो सकती है।आर्थिक दृष्टि से यह सत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। विदेशी निवेशक केवल आर्थिक आंकड़े ही नहीं देखते, बल्कि यह भी देखते हैं कि किसी देश की संसद कितनी स्थिरता और दक्षता से निर्णय लेने में सक्षम है। यदि महत्वपूर्ण आर्थिक विधेयक समय पर पारित होते हैं, तो इससे भारत की निवेश क्षमता और वैश्विक विश्वसनीयता मजबूत होगी। इसके विपरीत लगातार गतिरोध से निवेशकों में अनिश्चितता का संदेश जा सकता है। साथियों, भारतीय शेयर बाजार भी इस सत्र पर निकट दृष्टि रखे हुए है। बैंकिंग, कर सुधार, एमएसएमई विनिर्माण डिजिटल अर्थव्यवस्था और आधारभूत संरचना से जुड़े विधेयकों का सीधा प्रभाव विभिन्न क्षेत्रों के शेयरों पर पड़ सकता है। यदि सरकार सुधारवादी एजेंडा आगे बढ़ाने में सफल रहती है, तो दीर्घकाल में निवेशकों का विश्वास और मजबूत हो सकता है।अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी भारत का यह सत्र महत्वपूर्ण माना जा रहा है।भारत आज भी ज़ी-20 ब्रिक्स क्वाड तथा वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ऐसे में संसद की कार्यक्षमता यह संदेश देती है कि भारत केवल तेज़ आर्थिक विकास ही नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती के साथ भी आगे बढ़ रहा है। इसलिए विदेशी सरकारें, बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ और वैश्विक रेटिंग एजेंसियाँ भी इस सत्र के परिणामों पर नज़र रख रही हैं। साथियों, विज़न-2047 के संदर्भ में भी यह मानसून सत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है।विकसित भारत का लक्ष्य केवलआर्थिक वृद्धि से प्राप्त नहीं होगा; इसके लिए कर सुधार, औद्योगिक विस्तार,रोजगार सृजन, शिक्षा,कृषि,डिजिटल प्रशासन और राजनीतिक सहमति जैसे अनेक क्षेत्रों में निरंतर सुधार आवश्यक हैं। संसद इन सभी सुधारों का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक मंच है।

इसलिए अगले कुछ सप्ताहों में लिए जाने वाले निर्णय दूरगामी प्रभाव डाल सकते हैं। 20 जुलाई 2026 को शाम लगभग 5 बजे तक की स्थिति यह रही कि सदन का पहला दिन राजनीतिक टकराव की भेंट चढ़ गया। दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित हुई और अंततः पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। सरकार ने अपने विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाने की इच्छा दोहराई, जबकि विपक्ष ने स्पष्ट संकेत दिया कि वह जनहित और राजनीतिक मुद्दों पर व्यापक चर्चा के बिना सदन को सामान्य रूप से चलने नहीं देगा। साथियों, यदि भारतीय लोकतंत्र की कार्यप्रणाली का वैश्विक परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण किया जाए तो स्पष्ट होता है कि विश्व की लगभग सभी प्रमुख लोकतांत्रिकव्यवस्थाओं में संसद केवल कानून बनाने का मंच नहीं, बल्कि आर्थिक विश्वास का भी सबसे महत्वपूर्ण आधार होती है।

प्रकाशक एवं स्वामी सागर सूरज, द्वारा सरोतर निवास, राजाबाजार-कचहरी रोड, मोतिहारी, बिहार-845401 से प्रकाशित व प्रकाश प्रेस मोतिहारी से मुद्रित, संपादक-सागर सूरज* फोन न.9470050309 प्रसारः-9931408109 ईमेलः-bordernewsmirror@gmail.com वेबसाइटः-bordernewsmirror.com (*पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के लिए जिम्मेवार) RNI. N. BIHBIL/2022/88070

टी-20 में जीत की राह पर लौटने उतरेगा भारत, जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में अय्यर की अग्निपरीक्षा

एजेंसी, हरारे । लगातार टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद भारतीय टीम गुरुवार से शुरू हो रही तीन मैचों की टी-20 सीरीज में जिम्बाब्वे के खिलाफ जीत की पटरी पर लौटने के इरादे से मैदान में उतरेगी। कप्तान श्रेयस अय्यर अपनी कप्तानी में पहली सीरीज जीत दर्ज करने की कोशिश करेंगे, जबकि युवा भारतीय टीम के सामने हालिया असफलताओं को पीछे छोड़ने की चुनौती होगी। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारत ने शुरुआती सात टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में छह मैच गंवाए हैं। आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज हारने के बाद जिम्बाब्वे दौरा टीम के लिए आत्मविश्वास हासिल करने का सुनहरा मौका है। हालांकि भारत इस सीरीज में प्रबल दावेदार माना जा रहा है, लेकिन हार टीम के ड्रेसिंग रूम पर बड़ा असर डाल सकती है। इस दौरे पर मुख्य कोच गौतम गंभीर की जगह वीवीएस लक्ष्मण टीम की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। ऐसे में टीम संयोजन और रणनीति पर भी सभी की नजरें रहेंगी।

वैभव सूर्यवंशी पर रहेंगी निगाहें

युवा सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी एक बार फिर आकर्षण का

केंद्र होंगे। उनके साथ अभिषेक शर्मा पारी की शुरुआत करेंगे, जबकि संजू सैमसन इस दौरे के लिए टीम में शामिल नहीं हैं। हरारे स्पोर्ट्स क्लब का मैदान अभिषेक और वैभव दोनों के लिए खास रहा है। अभिषेक ने यहीं टी-20 अंतरराष्ट्रीय पदार्पण किया था और दूसरे ही मैच में शतक जड़ा था। वैभव ने इसी मैदान पर इस साल अंडर-19 विश्व कप फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ शानदार शतक लगाया था।

गेंदबाजी और मध्यक्रम सबसे बड़ी चुनौती

हरारे की पिच पर तेज गेंदबाजों को अतिरिक्त उछाल और मदद मिलने की संभावना है। ऐसे में जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरबानी और रिचर्ड नगरावा भारतीय बल्लेबाजों के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं। मध्यक्रम में उपकप्तान तिलक वर्मा की बल्लेबाजी क्रम को लेकर भी चर्चा है। उन्हें नंबर-5 पर सफलता नहीं मिली है, जबकि ईशान किशन नंबर-3 की भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे में रिंकू सिंह भी मध्यक्रम में मजबूत विकल्प माने जा रहे हैं। ऑलराउंडर संयोजन में हर्ष दुबे, शिवम दुबे और सूर्यांश शेडगे में से दो खिलाड़ियों का चयन करना टीम प्रबंधन के लिए आसान नहीं होगा। तेज गेंदबाजी आक्रमण में मयंक यादव, प्रिंस यादव, अशोक शर्मा और यश ठाकुर में से अंतिम संयोजन पर भी नजर रहेगी।

दोनों टीमें इस प्रकार हैं

भारतः श्रेयस अय्यर (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, हर्ष दुबे, सूर्यांश शेडगे, यश ठाकुर, प्रिंस यादव, मयंक यादव, अशोक शर्मा, रवि बिश्नोई, प्रभसिमरन सिंह, रिंकू सिंह।

जिम्बाब्वेः सिकंदर रजा (कप्तान), ब्रायन बेनेट, रियान बर्ल, तनाका चिवांगा, बेन करन, ब्रैड इवांस, वेस्ली मधेवेरे, तदिवानाशे मारुमानी, वेलिंगटन मसाकाद्जा, ब्लेसिंग मुजरबानी, डियोन मायर्स, रिचर्ड नगरावा, न्यूमैन न्यामहुरी, मिल्टन शुम्बा, तफाद्जवा त्सिगा।

दिलीप ट्रॉफी अगले माह शुरु होगी, रुतुराज करेंगे वेस्ट जोन की कप्तानी

एजेंसी, मुम्बई। बल्लेबाज रुतुराज गायकवाड़ अगले माह शुरु होने वाले घरेलू टूर्नामेंट दिलीप ट्रॉफी में वेस्ट जोन की कप्तानी करेंगे। वहीं बाएं हाथ के स्पिन ऑलराउंडर शम्स मुलानी टीम के उप-कप्तान होंगे। दिलीप ट्राफी मुकाबले 23 अगस्त से 10 सितंबर तक बेंगलुरु के बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) मैदान पर खेले जाएंगे। इसमे देश भर के उभरते हुए क्रिकेटर खेलते नजर आयेंगे। पिछले साल वेस्ट जोन की कप्तानी ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर ने की थी और टीम सेमीफाइनल तक पहुंची थी। हालांकि, सेंट्रल जोन से पहली पारी की बढ़त के कारण वे फाइनल में जगह नहीं बना पाए थे। इस

बार कप्तानी कर रहे रुतुराज का लक्ष्य टीम को जीत दिलाना रहेगा। गायकवाड़ इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के कप्तान रहे हैं। वह भारत ए टीम के भी कप्तान रहे हैं। उनकी कप्तानी के अनुभव से वेस्ट जोन को लाभ होगा। टीम में गायकवाड़ के अलावा, विस्फोटक सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ, के अलावा सरफराज खान और उनके भाई मुशीर भी शामिल हैं। इसके अलावा टीम में जयमीत पटेल और शिवालिक शर्मा को भी रखा गया है। वहीं गेंदबाजी विभाग की कमान मुलानी के पास रहेगी। जिन्हें ऑफ-स्पिन ऑलराउंडर तनुष कोटियन और बाएं हाथ के स्पिनर सिद्धार्थ देसाई का साथ मिलेगा। तेज गेंदबाज के तौर पर अनुभवी शार्दुल ठाकुर के अलावा तुषार देशपांडे, मुकेश चौधरी और ऑलराउंडर अतीत सेठ भी शामिल हैं।

बीसीसीआई ने घरेलू किकेट के लिए नीयमों में किया बदलाव

एजेंसी, मुम्बई। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने घरेल क्रिकेट के नीयमों में बदलाव की घोषणा कही है। बोर्ड ने आगामी 2026-27 घरेलू क्रिकेट सीजन के लिए खेल के नियमों में ये बदलाव इसे और बेहतर बनाने के लिए किये हैं। इसमें सबसे प्रमुख बदलाव ये है कि अगर कोई गेंदबाज जानबूझकर फ्रंट-फुट पर नो-बॉल या नॉन-लैंडिंग गेंद करता है, तो उसे केवल उस पारी से नहीं, बल्कि पूरे मैच से निलंबित कर दिया जाएगा। ये बदलाव खेल की अखंडता और रणनीतिक दुरुपयोग को रोकने के लिए किये गये है। ये बदलाव मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब (एमसीसी) की सिफारिशों को देखते हुए किया गया है। वहीं अब तक दोषी गेंदबाज को केवल उस पारी में गेंदबाजी करने की अनुमति नहीं होती थी। हालांकि, अब मैदानी अंपायर यदि यह निर्धारित करते हैं कि किसी गेंदबाज ने जानबूझकर फ्रंट-फुट नो-बॉल या नॉन-लैंडिंग गेंदबाज की है, तो उसे उस पूरे मैच में गेंदबाजी करने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। यह कदम खेल में अनुचित लाभ उठाने के प्रयासों को रोकने के लिए उठाया गया है। वहीं दिन के खेल के समाप्त होने से जुड़े नियम में भी बदलाव किया गया है। अब से, यदि दिन के आखिरी ओवर के दौरान कोई विकेट गिरता है, तो खेल वहीं समाप्त नहीं होगा।

भारत के उभरते ट्रिपल जंपर सेल्वा राष्ट्रमंडल खेलों में पदर्पण को लेकर हैं उत्साहित

एजेंसी, ग्लासगो । स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23 जुलाई से शुरु होने जा रहे राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के उभरते हुए ट्रिपल जंपर सेल्वा प्रभु पदार्पण के लिए पूरी तरह तैयार होने के साथ ही उत्साहित भी हैं। सेल्वा ने पिछले कुल समय में अच्छे प्रदर्शन से अपने को साबित किया है। इसी कारण उन्हें भारतीय दल में जगह मिली है। सेल्वा भी अपने करियर के सबसे बड़े मंचों में से एक पर देश का प्रतिनिधित्व करने को लेकर उत्साहित है। सेल्वा ने कहा कि उन्हें इसी दिन का इंतजार है जब वह भारतीय जर्सी पहनेंगे। उनका लक्ष्य अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना, और दुनिया के बेहतरीन एथलीटों

का मुकाबला करना है। सेल्वा के अनुसार अमेरिका में अत्यधिक प्रतिस्पर्धी एनसीएए सर्किट में बिताए गए पिछले कुछ साल का अनुभव उनके लिए यहां लाभदायक रहेगा। उन्होंने कहा कि एनसीएए में मुकाबला करने से उन्हें हर पहलू में आगे बढ़ने में मदद मिली है। वहां प्रतियोगिता का स्तर बहुत ऊंचा है, जिसने उन्हें तकनीकी, शारीरिक और मानसिक रूप से बेहतर बनने के लिए प्रेरित किया। सर्वश्रेष्ठ कोचों के साथ प्रशिक्षण और हर हफ्ते विश्व स्तरीय एथलीटों के खिलाफ मुकाबला करने से उनका आत्मविश्वास बढ़ा है और वे अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए वह उत्मविश्वास से भरे हुए हैं। सेल्वा ने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान प्रदर्शन में निरंतरता पर सबसे अधिक ध्यान दिया गया है। उनका मुख्य लक्ष्य अपनी गति, लय और तकनीक को बेहतर बनाने पर रहा है।

बिजनेस

अंतरराष्ट्रीय बाजार में दो महीने के टॉप लेवल पर क्रूड ऑयल, ब्रेंट क्रूड 92.63 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर पहुंचा

एजेंसी, नई दिल्ली

पश्चिम एशिया में लगातार बढ़ रहे तनाव खाड़ी देशों से कच्चे तेल की सप्लाई बाधित होने की वजह से अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। अमेरिका और ईरान के बीच जंग और तेज होने की आशंका के बीच ब्रेंट क्रूड आज दो महीने के ऊपरी स्तर पर पहुंच गया। आज ब्रेंट क्रूड ने तेजी दिखाते हुए 92 डॉलर प्रति बैरल के स्तर को पार कर लिया। इसी तरह वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) क्रूड भी आज एक बार फिर 85 डॉलर प्रति बैरल के स्तर को पार कर गया। अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड ने आज 0.45 डॉलर प्रति बैरल की मामूली उछाल के साथ 91.46 डॉलर प्रति बैरल के स्तर से कारोबार की शुरुआत की। ट्रेडिंग शुरू होने के बाद इसकी कीमत उछल कर 92.63 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर पहुंच गई। अंतरराष्ट्रीय बाजार में पिछले दो महीने के दौरान ब्रेंट क्रूड का ये सबसे ऊंचा स्तर है। हालांकि दिन के कारोबार में इसकी कीमत में

मामूली गिरावट भी आई। भारतीय समय के मुताबिक सुबह 11:30 बजे अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड 1.34 डॉलर प्रति बैरल यानी 1.48 प्रतिशत की तेजी के साथ 92.25 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर कारोबार कर रहा था। इसी तरह वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) क्रूड ने आज सिर्फ 0.15 डॉलर प्रति बैरल की सामान्य बढ़त के साथ 84.59 डॉलर प्रति बैरल के स्तर से आज के कारोबार की शुरुआत की। थोड़ी देर बाद ही डब्ल्यूटीआई क्रूड उछल कर 85.75 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर पहुंच गया। हालांकि बाद में इसकी कीमत में भी मामूली गिरावट दर्ज की गई। भारतीय समय के मुताबिक सुबह 11:30 बजे अंतरराष्ट्रीय बाजार में डब्ल्यूटीआई क्रूड 1.23 डॉलर प्रति बैरल यानी 1.46 प्रतिशत की तेजी के साथ 85.57 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर कारोबार कर रहा था। आपको बता दें कि अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर खत्म होने और पश्चिम एशिया में युद्ध तेज हो जाने की वजह से कच्चे तेल की कीमत में लगातार तेजी का रुख बना हुआ है। पिछले सप्ताह अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड 87 डॉलर प्रति बैरल के स्तर को पार कर एक महीने के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया था। इसी तरह डब्ल्यूटीआई क्रूड भी 81 डॉलर प्रति बैरल के स्तर के ऊपर चला गया था। इसके बाद ती दिन तक सुस्ती का माहौल बना रहा, लेकिन पिछले चार ट्रेडिंग सेशन से कच्चे तेल की कीमत में एक बार फिर तेजी का रुख बन गया है, जिसकी वजह से आज इसने पिछले दो महीने के सबसे ऊंचे स्तर को पार कर लिया है।

जानकारों का कहना है कि पश्चिम एशिया में बढ़ रहे तनाव की वजह से एक बार फिर कच्चे तेल की सप्लाई पर संकट बढ़ाने की आशंका बन गई है। टीएनवी फाइनेंशियल सर्विसेज के सीईओ तारकेश्वर नाथ वैष्णव का कहना है कि अमेरिका और ईरान के बीच जंग लगातार तेज हो रही है। दोनों पक्षों की ओर से लगातार हमले हो रहे हैं। इस बीच ईरान की ओर हूती विद्रोहियों ने भी मोर्चा संभालने का ऐलान कर दिया है। हूती विद्रोहियों ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका की ओर हो रहे हमले नहीं रुके तो वे रेड सी और बाब अल मंडेब जलडमरूमध्य के रास्ते जहाजों की होने वाली आवाजाही को ठप कर देंगे। हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब पर मैरीटाइम बैन भी लगा दिया है और शिप ओनर्स को सऊदी के बंदरगाहों पर नहीं आने की धमकी भी दी है।

अबतक 3 करोड़ से ज्यादा करदाताओं ने दाखिल किया रिटर्न

एजेंसी, नई दिल्ली

आकलन वर्ष 2026-27 के लिए अब तक तीन करोड़ से ज्यादा आयकर रिटर्न (आईटीआर) फाइल किए जा चुके हैं, जिनमें से अकेले 21 जुलाई को 15 लाख से ज्यादा रिटर्न दाखिल किए गए हैं। आयकर विभाग ने बुधवार को बताया कि आकलन वर्ष 2026-27 के लिए पहले ही 3 करोड़ से ज्यादा आईटीआर फाइल किए जा चुके हैं, जबकि अकेले मंगलवार, 21 जुलाई को ही 15 लाख से ज्यादा आईटीआर फाइल किए गए हैं।

डेडलाइन के समय होने वाली भीड़-भाड़ का इंतजार न करें। आकलन वर्ष 2026-27 के लिए अपना आईटीआर-1 और आईटीआर-2, 31 जुलाई 2026 से पहले http://incometax.gov.in पर फाइल करें। उल्लेखनीय है कि 31 जुलाई की डेडलाइन उन लोगों के लिए है, जिन्हें आईटीआर-1 और आईटीआर-2 फाइल करना है। आमतौर पर अगर आपकी सालाना आय इनकम टैक्स छूट की सीमा से ज्यादा है, तो आईटीआर फाइल करना जरूरी है।

नेस्ले इंडिया को पहली तिमाही का शुद्ध लाभ 958.68 करोड़ रुपये

एजेंसी, नई दिल्ली

दैनिक उपभोग की वस्तुएं बनाने वाली प्रमुख कंपनी नेस्ले इंडिया ने वित्त वर्ष 2026-27 की (अप्रैल-जून) पहली तिमाही के अपने नतीजे का ऐलान कर दिया है। नेस्ले इंडिया का अप्रैल-जून में एकीकृत शुद्ध लाभ (मुनाफा) 48.26 फीसदी बढ़कर 958.68 करोड़ रुपये हो गया। पिछले वित्त वर्ष 2025-26 की अप्रैल-जून तिमाही में उसका एकीकृत शुद्ध लाभ 646.59 करोड़ रुपये था। कंपनी ने बुधवार को शेयर बाजार को दी गई सूचना में बताया कि चालू वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में उत्पादों की बिक्री से नेस्ले इंडिया का राजस्व 25.4 फीसदी बढ़कर 6,363.27 करोड़ रुपये पर पहुचं गया, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 5073.96 करोड़ रुपये था। नेस्ले इंडिया के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) मनीष तिवारी ने कहा, ''हमने मात्रा वृद्धि के दम पर बिक्री में 25.4 फीसदी वृद्धि के साथ मजबूत तिमाही प्रदर्शन किया। बिक्री 6,363.3 करोड़ रुपये रही, जिसे हमारे ब्रांडों पर उपभोक्ताओं के निरंतर

भरोसे और प्रभावी क्रियान्वयन का समर्थन मिला। वहीं, भू-राजनीतिक चुनौतियों के बावजूद निर्यात में 35.6 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई।'' इसी तरह वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में नेस्ले इंडिया की कुल आय 25.5 फीसदी बढ़कर 6,400.65 करोड़ रुपये हो गई, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 5,100.33 करोड़ रुपये थी। कंपनी का कुल खर्च 20.71 फीसदी बढ़कर 5,070.03 करोड़ रुपये रहा। अप्रैल-जून तिमाही में घरेलू बिक्री 25 फीसदी बढ़कर 6,073.05 करोड़ रुपये हो गई, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में यह 4,860.01 करोड़ रुपये थी। वहीं, कंपनी का निर्यात राजस्व 35.64 फीसदी बढ़कर 290.22 करोड़ रुपये हो गया। तिवारी ने कहा कि पहली तिमाही के दौरान कंपनी ने परिचालन लागत में बचत के प्रयासों को और तेज करने के साथ अपने ब्रांडों में निवेश बढ़ाना जारी रखा। इसके अलावा विज्ञापन पर खर्च में 40 फीसदी से अधिक की वृद्धि की गई और कंपनी का कर पूर्व आय (ईबीआईटीडीए) मार्जिन 24.2 फीसदी रहा। नेस्ले इंडिया दैनिक उपभोग (एफएमसीजी) की एक प्रमुख कंपनी है। इस कंपनी का मुख्यालय गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित है। इसकी शुरुआत 1912 में हुई थी। ये मैगी, नेस्कैफे, किटकैट और सेरेलैक जैसे लोकप्रिय ब्रांड्स बनाती है। कंपनी के भारत में कुल 9 निर्माण संयंत्र हैं।

सब्सक्रिप्शन के लिए खुला श्री बालाजी माला टेक्सटाइल का आईपीओ, 29 जुलाई को हो सकती है लिस्टिंग

एजेंसी, नई दिल्ली

माला साड़ी ब्रांड की साड़ियों की निर्माता कंपनी श्री बालाजी (माला) टेक्सटाइल लिमिटेड का 18.90 करोड़ रुपये का आईपीओ आज सब्सक्रिप्शन के लिए लॉन्च कर दिया गया। इस आईपीओ में 24 जुलाई तक बोली लगाई जा सकती है। इश्यू की क्लोजिंग के बाद 27 जुलाई को शेयरों का अलॉटमेंट किया जाएगा, जबकि 28 जुलाई को अलॉटेड शेयर डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे।

कंपनी के शेयर 29 जुलाई को बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्ट हो सकते हैं। दोपहर 12:30 बजे तक ये आईपीओ 1.30 गुना सब्सक्राइब हो चुका था। इस

आईपीओ में बोली लगाने के लिए 66 रुपये से लेकर 70 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया गया है, जबकि लॉट साइज 2,000 शेयर का है। इस आईपीओ में रिटेल इनवेस्टर्स को दो लॉट यानी 4,000 शेयरों के लिए बोली लगाना होगा, जिसके लिए उन्हें 2,80,000 रुपये का निवेश करना होगा। इस आईपीओ के तहत 10 रुपये फेस वैल्यू वाले कुल 27 लाख नए शेयर जारी हो रहे हैं। इस आईपीओ में क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (क्यूआईबी) के लिए 47.19 प्रतिशत हिस्सा रिजर्व किया गया है। इसके अलावा रिटेल इनवेस्टर्स के लिए 33.33 प्रतिशत हिस्सा और नॉन इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स (एनआईआई) के लिए 14.44 प्रतिशत हिस्सा रिजर्व है।

सर्राफा बाजार में महंगा हुआ सोना, चांदी के भाव में मामूली गिरावट

एजेंसी, नई दिल्ली । घरेलू सर्राफा बाजार में आज शुरुआती कारोबार के दौरान सोने के भाव में तेजी का रुख बना हुआ नजर आ रहा है। दूसरी ओर, चांदी की कीमत में आज शुरुआती कारोबार के दौरान मामूली कमजोरी दर्ज की गई है। भाव में आए उछाल के कारण देश के ज्यादातर सर्राफा बाजार में सोना 700 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 760 रुपये प्रति 10 ग्राम तक महंगा हो गया है। वहीं चांदी के भाव में आज 200 रुपये प्रति किलोग्राम की सांकेतिक गिरावट नजर आ रही है। भाव में आए उछाल के कारण देश के ज्यादातर सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना आज 1,44,230 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 1,44,380 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह 22 कैरेट सोना आज 1,32,210 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 1,32,360 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच बिक रहा है। चांदी के भाव में प्रति किलोग्राम 200 रुपये की गिरावट आने के कारण ये चमकीली धातु दिल्ली सर्राफा बाजार में आज 2,34,900 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर बिक रही है। दिल्ली में 24 कैरेट सोना आज 1,44,380 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 1,32,360 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 24 कैरेट सोना 1,44,230 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,32,210 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है।

क्यूब हाइवेज ट्रस्ट का आईपीओ लॉन्च, 3 अगस्त को हो सकती है लिस्टिंग

एजेंसी, नई दिल्ली

रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए काम करने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्यूब हाइवेज ट्रस्ट इन्विट का 5,000 करोड़ रुपये का आईपीओ आज सब्सक्रिप्शन के लिए लॉन्च कर दिया गया। इस आईपीओ में 24 जुलाई तक बोली लगाई जा सकती है। इश्यू की क्लोजिंग के बाद 29 जुलाई को शेयरों का अलॉटमेंट किया जाएगा, जबकि 30 जुलाई को अलॉटेड शेयर डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। कंपनी के शेयर तीन अगस्त को बीएसई और एनएसई पर लिस्ट हो सकते हैं। पहले दिन दोपहर एक बजे तक ये आईपीओ सिर्फ दो प्रतिशत सब्सक्राइब हुआ है। इस आईपीओ में बोली लगाने के लिए 151 रुपये से लेकर

152 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया गया है, जबकि लॉट साइज 95 शेयर का है।

आईपीओ के तहत कुल 32,89,47,368 करोड़ शेयर ऑफर फॉर सेल विंडो के जरिये बेचे जा रहे हैं। आईपीओ में क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (क्यूआईबी) को अधिकतम 75 प्रतिशत शेयर अलॉट किए जाएंगे, जबकि नॉन इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स (एनआईआई) को न्यूनतम 25 प्रतिशत शेयर दिए जाएंगे। इस इश्यू के लिए कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी लिमिटेड को बुक रनिंग लीड मैनेजर बनाया गया है, जबकि केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को रजिस्ट्रार बनाया गया है।

बस 3 दिन बाकी : जन नेता का दमदार नया पोस्टर आउट, एडवांस बुकिंग को मिला शानदार रिस्पॉन्स

भारतीय सिनेमा के इतिहास में कुछ ऐसी फिल्में आती हैं, जो रिलीज से पहले ही एक आंदोलन का रूप ले लेती हैं। तमिलनाडु के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री और दक्षिण भारतीय सिनेमा के महानायक सुपरस्टार थलपति विजय की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'जन नेता' (मूल तमिल नामः जन नायकन) इसका सबसे ताजा और जीवंत उदाहरण है। 23 जुलाई 2026 को दुनियाभर के थियेटरों में दस्तक देने जा रही इस फिल्म को लेकर दर्शकों और समीक्षकों के बीच अभूतपूर्व उत्साह देखा जा रहा है। फिल्म की रिलीज में जब अब कुछ ही घंटे शेष रह गए हैं, तो निर्माताओं ने इसका एक बेहद दमदार और नया पोस्टर जारी कर दिया है, जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। इसके साथ ही, बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की एडवांस बुकिंग के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, वे इस बात का साफ संकेत हैं कि 'जन नेता' पहले ही दिन कमाई के कई बड़े रिकॉर्ड ध्वस्त करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

फिल्म के निर्माताओं (KVN Productions और ज़ी स्टूडियोज) द्वारा जारी किया गया नया पोस्टर अपने आप में एक पूरी कहानी बयां कर रहा है। इस नए विजुअल में फिल्म के मुख्य नायक थलपति विजय एक बेहद कड़क और अनुशासित पुलिस अधिकारी की वर्दी में नजर आ रहे हैं, वहीं उनके ठीक सामने बॉलीवुड के 'लॉर्ड' कहे जाने वाले बॉबी देओल खड़े हैं। पोस्टर में दोनों ही कलाकारों के चेहरे के भाव इतने उग्र और गंभीर हैं कि दोनों के बीच होने वाले वैचारिक और शारीरिक टकराव की तीव्रता को साफ महसूस किया जा सकता है।समीक्षकों का मानना है कि यह पोस्टर केवल एक प्रचार सामग्री नहीं है, बल्कि यह फिल्म के मुख्य आकर्षण—यानी विजय और बॉबी देओल के महा-मुकाबले—को रेखांकित करता है। पोस्टर के बैकग्राउंड में एक राजनीतिक और सामाजिक अशांति की झलक दिखती है, जो फिल्म के नाम 'जन नेता' को पूरी तरह सार्थक करती है। इंटरनेट पर इस पोस्टर के आते ही फैंस ने इसे हाथों-हाथ लिया है और कुछ ही घंटों में यह विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नंबर वन ट्रेंड बन गया है। यदि बात एडवांस बुकिंग की करें, तो 'जन

नेता' ने बॉक्स ऑफिस पर एक तरह की सुनामी ला दी है। आधिकारिक रिपोर्ट्स के अनुसार, फिल्म ने रिलीज से पहले ही भारत में केवल 15.09 करोड़ रुपये से अधिक की बंपर एडवांस बुकिंग ग्रॉस (ब्लॉक सीटों को मिलाकर) दर्ज कर ली है। एडवांस टिकटों की कुल बिक्री पहले ही 5 लाख से अधिक का आंकड़ा पार कर चुकी है, जो किसी भी भारतीय फिल्म के लिए एक शानदार शुरुआत मानी जाती है।इस ऐतिहासिक बुकिंग में सबसे बड़ा योगदान इसके मूल तमिल संस्करण का है, जिसने 5,000 से अधिक शोज के लिए लगभग 4.17 लाख टिकट बेचकर अकेले 10.22 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है। इसके बाद तेलुगु डब संस्करण 'जन नायकुडु' का नंबर आता है। उत्तर भारत की बात करें तो हिंदी डब संस्करण 'जन नेता' की शुरुआत थोड़ी धीमी जरूर हुई थी, लेकिन जैसे ही नया पोस्टर और अंतिम ट्रेलर सामने आया, उत्तर भारत के मल्टीप्लेक्स जैसे PVR, INOX और सिनेपोलिस में टिकटों की मांग में भारी उछाल देखा गया है। फिल्म व्यापार विश्लेषकों का अनुमान है कि यह फिल्म दुनिया भर में अपने पहले ही दिन 100 करोड़ रुपये की ओपनिंग छू सकती है। इस फिल्म को लेकर दीवानगी का आलम यह है कि देश के अलग-अलग हिस्सों में टिकट की कीमतों में भारी असमानता देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां थलपति विजय के गृह राज्य तमिलनाडु में सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के तहत टिकट की कीमतें 54 से 190 के बीच बेहद किफायती रखी गई हैं, वहीं दूसरी तरफ बेंगलुरु, हैदराबाद और मुंबई जैसे मेट्रो शहरों में क्रेज सातवें आसमान पर है। बेंगलुरु के कुछ चुनिंदा मल्टीप्लेक्सों में इसके प्रीमियम रिक्लाइनर सीटों की कीमत 2,500 तक पहुंच गई है, इसके बावजूद वीकेंड के शोज तेजी से 'हाउसफुल' (Almost Full) हो रहे हैं। चेन्नई के मशहूर मायाजाल मल्टीप्लेक्स ने तो रिलीज के पहले दिन के अपने सभी 48 शोज एडवांस में ही पूरी तरह बेच दिए हैं। निर्देशक एच. विनोथ के निर्देशन में बनी यह फिल्म एक बेहद संवेदनशील और मजबूत विषय पर आधारित है। सूत्रों के अनुसार, यह फिल्म तेलुगु की ब्लॉकबस्टर हिट 'भगवंत केसरी' से प्रेरित है। कहानी में विजय एक ऐसे पूर्व पुलिस अधिकारी और संरक्षक की भूमिका में हैं, जो अपने अतीत के संघर्षों को भुलाकर एक बच्ची (ममिथा बैजू द्वारा अभिनीत) को समाज के क्रूर दुश्मनों और भ्रष्ट व्यवस्था से लड़ना सिखाते हैं। फिल्म में पूजा हेगड़े और गौतम वासुदेव मेनन भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में नजर आएंगे।फिल्म का संगीत दक्षिण सिनेमा के रॉकस्टार अनिरुद्ध रविचंदर ने तैयार किया है, जिसके गाने पहले ही चार्टबस्टर साबित हो चुके हैं। चूंकि फिल्म में हाई-ऑक्टेन एक्शन और भारी हिंसा देखने को मिलने वाली है, इसलिए सेंसर बोर्ड ने इसे 'A' (Adults Only) सर्टिफिकेट के साथ पास किया है। यह सर्टिफिकेट भी वयस्कों के बीच फिल्म के प्रति कौतूहल को और बढ़ा रहा है।देशभर के 2,500 से अधिक स्क्रीन्स पर रिलीज होने जा रही 'जन नेता' न केवल थलपति विजय के फिल्मी करियर का एक शानदार अंत होने जा रही है, बल्कि यह भारतीय बॉक्स ऑफिस पर कमाई के एक नए युग की शुरुआत भी कर सकती है। अब सभी की नजरें कल सुबह होने वाले पहले शो और दर्शकों के शुरुआती रिव्यू पर टिकी हुई हैं।

राजनीति में एंट्री से पहले थलपति विजय की 'आखिरी सिनेमाई जंग''

जन नेता' को लेकर केवल सिनेमाई दर्शकों में ही नहीं, बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी भारी उत्सुकता है। तीन दशकों से अधिक समय तक तमिल सिनेमा पर राज करने वाले जोसेफ विजय ने हाल ही में राजनीति में कदम रखा है और उनकी पार्टी ने बड़ी सफलता हासिल की है। इस फिल्म को थलपति विजय की एक अभिनेता के रूप में आखिरी थियेट्रिकल रिलीज के रूप में देखा जा रहा है। इसके बाद वे अभिनय से पूरी तरह संन्यास लेकर अपना पूरा समय जनता की सेवा और राजनीति को देने वाले हैं। यही कारण है कि उनके करोड़ों फैंस इस फिल्म को एक विदाई उत्सव की तरह मना रहे हैं। थियेटरों के बाहर 100-100 फीट ऊंचे कटआउट्स लगाए जा रहे हैं और सुबह 4 बजे के अर्ली मॉर्निंग शोज का आयोजन किया जा रहा है।

महानायक की सर्जरी के बाद घर वापसी : रिकवरी को बताया जीवन का सबसे मुश्किल दौर

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन हाल ही में सर्जरी के बाद घर लौट आए हैं, जिसके बाद उन्होंने अपने ताजा ब्लॉग में अनुभव को जीवन का अब तक का सबसे मुश्किल दौर बताया है। दिग्गज अभिनेता को सर्जरी के बाद कुछ समय के लिए आईसीयू में रहना पड़ा था, और अब घर वापसी पर शारीरिक, मानसिक और व्यावहारिक स्तर पर भी रिकवरी की अप्रत्याशित चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।

अपने ब्लॉग में, बच्चन ने बताया कि अस्पताल में सर्जरी और आईसीयू में डॉक्टरों की कड़ी निगरानी से बाहर आने के बाद घर लौटना कितना जटिल और कठिन होता है। उन्होंने लिखा कि इस दौरान उन्हें कई इसतरह के संघर्षों से जूझना पड़ा जो उनकी शारीरिक क्षमता के साथ-साथ उनके मानसिक धैर्य की परीक्षा ले रहे थे। हालांकि, बिग बी ने इसका खुलासा नहीं किया कि उन्होंने किस विशिष्ट प्रकार की सर्जरी कराई थी, जिससे उनके करोड़ों प्रशंसकों के बीच उनकी सेहत को लेकर चिंता बढ़ गई हैं। मुश्किलों और हार का सामना करने के विषय पर कुछ गहरे दार्शनिक विचार साझा करते हुए, अमिताभ बच्चन ने लिखा, आप एक सम्मानित चैंपियन होते हैं और एक दिन अचानक हार आपके सामने एक चुनौती बनकर खड़ी होती है....यह आपकी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल दौर होता है। उन्होंने कहा कि इसतरह के कठिन क्षणों से कुछ लोग अदम्य साहस और दृढ़ता के साथ उबरने में कामयाब होते हैं, जबकि कुछ अन्य अपनी पिछली सफलताओं और गौरवशाली यादों में ही खोए रहते हैं और आगे बढ़ने से कतराते हैं। उन्होंने खुद को और अपने सभी पाठकों को भी, हर हाल में हिम्मत बनाए रखने, डटे रहने और लगातार प्रयास करने के लिए प्रेरित किया। अपने ब्लॉग का समापन कर बच्चन ने संक्षिप्त संदेश में लिखा, स्वस्थ रहें, खुश रहें बस यही सब है। हालांकि उन्होंने अपनी वर्तमान सेहत के बारे में और कोई विस्तृत जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन सोशल मीडिया पर उनके लाखों प्रशंसक उनके शीघ्र स्वस्थ होने और पूरी तरह से ठीक होने की कामना करते हुए लगातार हार्दिक संदेश और शुभकामनाएं भेज रहे हैं।

प्रीति जिंटा ने साझा किया पति संग फीफा वर्ल्ड कप फाइनल की तस्वीरें

बॉलीवुड अभिनेत्री प्रीति जिंटा ने हाल ही में फीफा विश्व कप 2026 के रोमांचक फाइनल मुकाबले की कुछ खास तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की हैं, जिसमें वह अपने पति जीन गुडइनफ के साथ स्टेडियम में मैच का भरपूर आनंद लेती नजर आ रही हैं। इस दौरान उन्होंने विजेता टीम स्पेन को हार्दिक बधाई भी दी। प्रीति जिंटा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फाइनल मुकाबले की कई तस्वीरें शेयर करते हुए बताया कि अपने पति और द गुड इनफ बॉयज (संभवतः अपने दोस्तों के समूह) के साथ न्यू जर्सी में यह ऐतिहासिक मैच देखना उनके लिए बेहद यादगार अनुभव रहा। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, इस बार का वीकेंड बेहद खास और मजेदार रहा। न्यू जर्सी में द गुड इनफ बॉयज के साथ फीफा विश्व कप का फाइनल देखने का शानदार मौका मिला।

प्रीति ने इस फाइनल मुकाबले को किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं बताया और इसके पीछे की दिलचस्प वजह भी साझा की। उन्होंने लिखा, यह फाइनल किसी फिल्मी कहानी जैसा लगा। पिछली बार की विश्व विजेता अर्जेंटीना का मुकाबला स्पेन से था, जो मार्च 2024 के बाद से कोई अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं हारा था। उन्होंने युवा स्पेनिश स्टार खिलाड़ी लैमिन यामल और अर्जेंटीना के महान खिलाड़ी लियोनेल मेसी के

बीच एक अनोखे संयोग का भी जिक्र किया, जिसने मैच की कहानी को और भी दिलचस्प बना दिया। प्रीति ने बताया, उनकी युवा स्टार खिलाड़ी लैमिन यामल वही खिलाड़ी हैं, जिनकी पांच महीने की उम्र में लियोनेल मेसी के साथ खिंची तस्वीर काफी वायरल हुई थी। उस तस्वीर में मेसी उन्हें एक प्लास्टिक के टब में नहलाते नजर आए थे। उन्होंने आगे इस संयोग पर हैरानी जताते हुए लिखा, एक बार फिर किस्मत का खेल देखिए, दोनों टीमें विश्व कप फाइनल में आमने-सामने थीं। ऐसी कहानी कौन लिख सकता है? अभिनेत्री ने अपने अनुभव को साझा करते हुए कहा, मैं बस इतना कह सकती हूं कि अपने पति के साथ स्टेडियम में बैठकर इस मुकाबले का हिस्सा बनना मेरे लिए बेहद यादगार अनुभव रहा। उन्होंने स्पेनिश टीम और उसके सभी प्रशंसकों को फीफा विश्व कप जीतने की बहुत-बहुत बधाई दी और कहा, इस ऐतिहासिक मुकाबले को देखना वाकई शानदार अनुभव था। टूर्नामेंट के फाइनल में, स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर फीफा विश्व कप 2026 का खिताब अपने नाम किया। अतिरिक्त समय में फेरान टोरेस द्वारा किए गए विजयी गोल की बदौलत स्पेन ने 16 साल के लंबे अंतराल के बाद दूसरी बार विश्व कप जीता, जिसने इतिहास रच दिया। इस बार का टूर्नामेंट कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका की संयुक्त मेजबानी में आयोजित किया गया था, जिसमें पहली बार 48 टीमों ने हिस्सा लिया, जो इसे फीफा विश्व कप के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे समावेशी संस्करण बनाता है। प्रीति जिंटा जैसे सितारों की मौजूदगी ने इस वैश्विक खेल आयोजन की चमक को और बढ़ा दिया।

बॉलीवुड स्टार किड ने किया 'धुरंधर' एक्ट्रेस को रिप्लेस

बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर' से सारा अर्जुन रातों-रात स्टार बन गई हैं. इस फिल्म में सारा की एक्टिंग की खूब तारीफ हुई. वहीं इसके बाद वे गुनाशेखर की तेलुगु फिल्म 'यूफोरिया' में नजर आई हैं. वहीं 'श्रीनिवास मंगपुरम' के लिए भी मेकर्स की पहली पसंद थीं. इस फिल्म से महेश बाबू के भतीजे जयकृष्ण घट्टामनेनी डेब्यू कर रहे हैं. वहीं अब सारा की जगह इस अपकमिंग फिल्म में फीमेल लीड के लिए एक स्टार किड को कास्ट किया गया है. एक इंटरव्यू में डायरेक्टर अजय भूपति ने कहा, "हां, हमने उनके (सारा अर्जुन) बारे में सोचा था. मुझे लगा कि उस समय वह यह रोल निभाने के लिए बहुत छोटी थीं. तब तक 'धुरंधर' रिलीज़ नहीं हुई थी. मुझे लगता है कि कास्टिंग एजेंसी के साथ भी कुछ दिक्कतें थीं." रवीना टंडन की बेटी राशा थडानी 'श्रीनिवास मंगपुरम' से तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू कर रही हैं. अजय भूपति ने बताया कि उन्होंने राशा के यूट्यूब वीडियो देखने के बाद उन्हें कास्ट किया और वह उनकी एक्टिंग स्किल्स से काफी इम्प्रेस थे. क्या यह प्रोजेक्ट राशा के लिए एक सफल लॉन्चपैड साबित होगा? यह तो समय ही बताएगा. बता दें कि प्रोड्यूसर पी. किरण की इस फ़िल्म को अश्विनी दत्त प्रेजेंटर कर रहे है और यह 30 जुलाई को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी. इसमें मोहन बाबू विलेन का रोल निभा रहे हैं, जबकि जीवी प्रकाश ने इसका म्यूज़िक तैयार किया है. बता दें कि सारा अर्जुन ने रणवीर सिंह स्टारर साल 2025 के दिसंबर में आई धुरंधर में काम किया था. ये फिल्म ब्लॉकबस्टर रही थी और इसने दुनियाभर में 1307 करोड़ की कमाई की थी. इसके बाद मार्च 2026 में आई धुरंधर 2 में भी सारा अर्जुन फीमेल लीड में नजर आई थीं. धुरंधर 2 ने भी बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे इसने वर्ल्डवाइड 18सौ करोड़ से ज्यादा कमाई की है.

800 करोड़ी फिल्म की शूटिंग छोड़ हसीन वादियों में पहुंचे अल्लू अर्जुन, परिवार संग बीता रहे वक्त

साउथ एक्टर अल्लू अर्जुन की 'पुष्पा 2' की बड़ी सक्सेस के बाद से कोई फिल्म नहीं आई है और फैंस उन्हें अब बड़े पर्दे पर देखने के लिए बेताब हैं. हालांकि वो अपने फैंस के लिए खास तैयारी कर रहे हैं. दरअसल इन दिनों उनके पास एटली की बिग बजट फिल्म 'राका' है. एक्टर इसकी शूटिंगं में बिजी हैं, लेकिन फिलहाल उन्होंने इससे ब्रेक लिया है और अपने

परिवार के साथ वो विदेश घूमने के लिए निकल गए हैं. हाल ही में वो परिवार के साथ हसीन वादियों का लुत्फ लेते हुए नजर आए. अल्लू अर्जुन की सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिनमें वो अपनी पत्नी स्नेहा रेड्डी और बच्चों के साथ नजर आ रहे हैं. इन तस्वीरों को उनकी पत्नी स्नेहा ने इंस्टाग्राम स्टोरी में शेयर किया है. बता दें कि राका की शूटिंग से ब्रेक लेकर अल्लू फिलहाल पूरा वक्त अपने परिवार को दे रहे हैं. बता दें कि अल्लू अर्जुन वायरल तस्वीरों और वीडियो में ऑस्ट्रियन आल्प्स में नजर रहे हैं. इसे यूरोप के सबसे खूबसूरत और ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में से एक माना जाता है. यहां बड़ी संख्या में लोग प्रकृति की खूबसूरती का आनद लेने के लिए पहुंचते हैं. तस्वीरों और वीडियो में अल्लू अपनी पत्नी स्नेहा, बेटे अयान और बेटी अरहा के साथ दिखाई दे रहे हैं.

ये खूबसूरत जगह समुद्र तल से लगभग 1,905 मीटर की ऊंचाई पर है. इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है. साउथ एक्टर ने कभी अपनी पत्नी के साथ पोज दिया तो कभी बच्चों के साथ तस्वीरें क्लिक कराईं. इस दौरान वो कार्गो पैंट, सफ़ेद स्नीकर्स और बॉम्बर जैकेट में नजर आए. छुट्टियों से लौटने के बाद अल्लू अर्जुन दोबारा से अपनी फिल्म राका की शूटिंग शुरू करेंगे. इसका डायरेक्शन 'जवान' फिल्म बनाने वाले एटली कर रहे हैं. इस फिल्म में उनके साथ बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण नजर आएंगी. ये पहला मौक़ा होगा जब दोनों स्क्रीन शेयर करेंगे. पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक इसका बजट 800 करोड़ रुपये है.

Indus Water Treaty in present form no longer exists, Pak aiding terrorism: India

New Delhi, Agency: The Indus Waters Treaty (IWT) with Pakistan will no longer function in its present form, the government has concluded hardening its position on the contentious water issue amid little indication of Islamabad discontinuing its covert backing of cross-border terrorism.

India is not yet actively considering abandoning the World Bank-brokered 1960 Treaty - an option it still has on the table - but a source speaking on condition of anonymity said it's not in India's interest to remain a party to the Treaty anymore.

India had formally sought a review and modification of the IWT citing demographic shifts, clean energy priorities and new climate realities, prior to putting the Treaty in "abeyance" last year in retaliation for the Pahalgam terrorist attack.

"It would be accurate to say that the IWT in its present form will not function at all. If provisions related to river water sharing have to be reactivated, they will have to be done in a different form. Not in the present form," said the source, adding India will await further developments before considering the maximalist option of withdrawing altogether from the IWT.

The IWT does not have an exit clause, but it's of significance to India that Article 60 of the Vienna Convention on the Law of Treaties (VCLT) states that a significant violation of a treaty by

one party allows other affected parties to suspend the treaty in whole or in part. While India and Pakistan are both not party to the VCLT, India believes that if it invoked customary international law, then Pakistan's state sponsorship of terrorism could be considered such a breach of obligations.

According to Indian authorities, as a sovereign state, India cannot be compelled to stay in a treaty that is demonstrably not in its interest. These assertions come in the middle of efforts by Pakistan to internationalise the IWT issue by citing "unilateral and unlawful" suspension of the Treaty and claiming it threatens the water security and livelihoods of its 240 million citizens. Outside of the Treaty framework, India continues to provide issue flood warnings to Pakistan to ensure protection of lives and property.

India believes that Pakistan has created an elaborate victimhood narrative, ignoring the fact that more water of the Indus system is lost in Pakistan due to surface runoff than India's entire share under the Indus water stream. Sources also point to how Pakistan has since 1976 not built a single large-scale storage project or invested in modern water management, despite receiving nearly 80% of the Indus Basin waters under the Treaty. As far as India is concerned, Pakistan's problem is water management, and not water availability.

Fow India though, the central issue remains Pakistan's support to cross-border terrorism. India maintains that there is no deadline for keeping the IWT in abeyance. "The Treaty will remain in abeyance until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. This is the threshold condition," said a source, adding that Pakistan continues to provide enabling platforms just across the LoC to terrorist groups and individuals banned by the UNSC 1267 Sanctions Committee.

DIG orders probe into allegations against Banjariya SHO

Sagar Suraj

DIG orders inquiry into corruption, abuse of office allegations against Banjariya SHO; seeks report on claims of favouring accused and leak of confidential supervision report

MOTIHARI: Deputy Inspector General (DIG) of Champaran Range Harkishor Ray has ordered a detailed inquiry into allegations of corruption, abuse of office and alleged collusion with land mafia against Banjariya station house officer (SHO) Amit Kumar Singh.

Acting on a complaint submitted by the victim's family on Wednesday, the DIG directed East Champaran superintendent of police (SP) Swarn Prabhat to investigate all allegations against the SHO and submit a factual report.

The allegations took another turn when the complainant produced a copy of a supervision report prepared by Sadar deputy superintendent of police (DSP) Dilip Kumar.

Taking serious note of the confidential document being in the complainant's possession, the DIG

questioned how the report had been obtained and directed the SP to investigate the alleged leak.

He also ordered that responsibility be fixed if any police personnel were found to have shared the confidential report.

The DIG simultaneously directed the SP to independently verify the allegations made in the complaint.

In their petition to the DIG and the SP, one Izhar Ansari and his family alleged that despite an inquiry reportedly substantiating their complaint involving fraud, forgery, criminal breach of trust and an attempt to grab their land, the SHO failed to initiate action against the accused.

Instead, they alleged, false criminal cases were lodged against members of the complainant's family to protect the accused.

The complainants further claimed that the supervision note prepared by Sadar DSP Dilip Kumar contained adverse observations on the SHO's conduct, stating that his actions appeared to benefit the accused.

According to the complaint, after Case No. 521/26 was reportedly found to be true during investigation, the accused demolished one of the family's houses.

They also alleged that Shamser Alam's wife was assaulted and abused while trying to resist the demolition. Despite the availability of CCTV footage, the complainants alleged that Banjariya police refused to register an FIR.

The family alleged that they repeatedly approached the police station to lodge a complaint, but the SHO refused to accept their application.

Instead, they claimed, another FIR was registered against Izhar Ansari and Shamser Alam on the basis of a fabricated medical report, and they were threatened with arrest.

The complainants also alleged that despite repeatedly approaching the SP and the DSP, and despite directions reportedly being issued to the police station, no FIR was registered and they continue to face intimidation.

When contacted, Banjariya SHO Amit Kumar Singh declined to comment on the allegations, saying, "I am answerable only to my senior officers."

Meanwhile, Rajeev Dwivedi, general secretary of the District Bar Association, said it was not uncommon for clients to approach lawyers with copies of confidential supervision reports. Such reports, he said, remain confidential departmental documents until a charge sheet or final report is filed before a court. He alleged that investigating officers often leak such reports in exchange for money.

Following the hearing, the DIG directed the SP to also investigate how the confidential supervision report reached the complainant and to take appropriate action if any departmental lapse is established.

Future of youth priority: PM Modi says NEET leak national issue, avoid 'partisan politics

New Delhi, Agency: Union minister Kiren Rijiju Tuesday said PM Narendra Modi, during the NDA's parliamentary party meeting, retierated government's stance to ensure "stringent punishment" for those involved in the NEET paper leak.

Rijiju, who is the minister of parliamentary affairs, said the Prime Minister stated that "NEET paper leak should not be an issue of partisan politics".

PM Modi, according to Rijiju, also said that "security and future of youth" is the government's priority.

The Prime Minister's reaction comes in the backdrop of youth, led by Cockroach Janta Party (CJP), protesting against the perpetual paper leaks, and alleged irregularities in the education system.

The uproar over the NEET leak and lack of accountablity at the senior-most level exploded in the Captial on Monday as protestors, mostly students and youths, clashed with police -- leading the cops to resort to lathi charge, firing of tear gas to disperse the protesting crowd marching towards the Parliament.

The protestors had three main demands: Resignation of Union education of minister Dharmendra Pradhan, discharging Sonam Wangchuk from hospital and providing compensation to the kin of NEET aspirants who died by suicide after the leak froced the governemnt to reexamination

Supreme Court takes exception to meagre compensation for ex-HC judges

New Delhi, Agency: Supreme Court Monday took exception to the meagre monetary compensation provided to retired chief justices and judges of high courts, which varies vastly from one state to another, and asked the Union govt to constitute a committee to lay down uniform pan-India guidelines.

A bench of CJI Surya Kant and Justices Joymalya Bagchi and V Mohana took exception to the UP govt's challenge to an interim order of Allahabad HC directing the state to provide security even though it is paying Rs 65,000 and Rs 60,000 to retired CJs and judges of the HC towards security, a driver, domestic help, secretarial services, and telephone and internet expenses. The bench said HC judges, while holding constitutional posts, decide sensitive matters and their apprehensions about personal security are genuine. "Post-retirement, the judges need basic minimum facilities to lead a dignified life. Can Rs 60,000 provide all these services? We all know how much one needs to pay to employ a driver and a domestic help," the CJI-led bench said. Finding solicitor general Tushar Mehta in the courtroom, the bench asked him to impress upon Centre to constitute a committee in two weeks to consider what should be the basic minimum security and services that every state must provide to retired HC CJs and judges to enable them to lead a dignified life.

India summons Russian diplomat over 4 Indians killed in strike off Ukranian coast

New Delhi, Agency: India on Tuesday summoned Russian diplomat over the killing of four Indians on board a merchant vessel off the coast of Ukraine, reported news agency PTI citing sources.

Four Indian nationals were killed after a commercial vessel, MV Golden Leo, came under attack while departing Ukraine's port of Odesa on Sunday, the Indian government confirmed. One more Indian crew member remains in critical condition.

According to the government, the vessel had 17 crew members on board, including five Indian

nationals, when it was attacked.

India strongly condemned the strike, saying attacks on commercial shipping and civilian crew members were unacceptable.

India, in a statement, said, "As per the information available, four Indian nationals have tragically lost their lives, while one is hospitalised in a critical condition. Our mission in Ukraine is closely monitoring the situation and is making every effort to extend all possible assistance to those affected."

The government also reiterated that targeting commercial vessels, endangering civilian seafarers and disrupting freedom of navigation and international trade was deplorable and should be avoided.

One of those killed has been identified as 26-year-old merchant navy officer Akhil Joyan from Vellarikkundu in Kerala's Kasaragod district. His family was informed of his death by the shipping company through an email on Monday.

J&K floods: Lal Chowk flooded, Amarnath yatra stays suspended

SRINAGAR, Agency: :A heavy spell of rainfall Monday morning inundated Srinagar's Lal Chowk, the city's iconic square that has emerged as a major tourist attraction since the abrogation of Article 370.

Images of a flooded Lal Chowk and the clock tower were widely circulated on social media, with netizens mocking the govt over the alleged failure of the drainage system in the city.

Several other parts of Srinagar also witnessed waterlogging, with many questioning Srinagar's Smart City infrastructure project.

Officials of the Srinagar Municipal Corporation (SMC) said the capital city's drainage system was overwhelmed by the intensity of the rainfall. "It was a heavy downpour for nearly two hours," an official said, adding that dewatering pumps were deployed to clear waterlogged areas.

The explanation, though, was shot down by many.

"The idea of a Smart City is to employ technologies, data and intelligent systems to improve efficiency, sustainability, quality of life and resource management with the approval of the citizens. Smart City Srinagar was based on contextless, soulless and photoshopped images," said Hakim Sameer Hamdani, a conservation architect. "We need to have a way to manage run-off water from the road and ideally that should be treated and used to recharge groundwater. But there is no proper and integrated system," Hamdani said. SMC officials, however, said all works sanctioned under the Srinagar Smart City project, which began in April 2017, were completed.

Last month, the Omar Abdullah cabinet raised concerns about the award of contracts and the implementation of projects under the Smart City initiative. His govt ordered an external audit on the "failure of the Srinagar Smart City" project.